bjpkamaljyoti@gmail.com www.up.bjp.org संवत 2081 युगाब्द 5126 कुल पृष्ठ–32, मार्च द्वितीय अंक 2025, वर्ष–36 : अंक–16

वर्तमान

कमल ज्योति

सर्वोत्तम उत्तर प्रदेश

⇨ सबका साथ
⇨ सबका विकास

₹20

हर हिन्दुस्तानी को गर्व होता है, जब हम सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश ने ठान लिया है कि एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे। मैं देश के सभी राज्यों से आग्रह करूंगा, राजनीति अपनी जगह पर छोड़िये, जरा उत्तर प्रदेश से सीखिए। मुझे अपने यूपी के परिवारजनों के सामर्थ्य और डबल इंजन सरकार के परिश्रम पर पूरा विश्वास है। आज जो आधारशिला रखी गई है वो यूपी और देश की प्रगति की आधारशिला बनेगी, और मैं योगी जी को, उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष बधाई देता हूं।

– नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार राज्य में अंत्योदय के संकल्प के साथ प्रगति और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए आयाम स्थापित कर रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'विकसित भारत' की संकल्प यात्रा में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभाएगा।

– जगत प्रकाश नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन में सुशासन के मंत्र, गरीब कल्याण के संकल्प, समृद्धि के विजन, अंत्योदय के दर्शन और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लक्ष्य के साथ अविराम जारी 'कर्तव्य-साधना' के इन आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश 'कायाकल्प' के केंद्र के रूप में देश में स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश आज 'ग्रोथ गियर, गुड गवर्नेंस और गवर्निंग ग्रिट' के साथ देश का ग्रोथ इंजन, डेवलपमेंट हब बन गया है। उत्तर प्रदेश की यह यात्रा संकल्प से सिद्धि की यात्रा है। हमारी नीति और नीयत साफ है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ है।

– योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रभावी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने बीते आठ वर्षों में सुशासन, सुरक्षा और समग्र विकास की नई ऊंचाइयां छुआ है। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने प्रदेश को माफिया राज, अराजकता और पिछड़ेपन से मुक्त कर, कानून-व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, निवेश और गरीब कल्याण में नए मानदंड स्थापित किए हैं। यह बदलता उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता एक मजबूत कदम है।

– भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा

वर्तमान
कमल ज्योति

संरक्षक
श्री भूपेन्द्र सिंह
सम्पादक
अरुण कान्त त्रिपाठी
प्रबन्ध/कार्यकारी सम्पादक
राजकुमार
प्रकाशक
प्रो0 श्याम नन्दन सिंह
पृष्ठ संयोजक
ओम प्रकाश पंडित

कार्यालय

कमल ज्योति, 7–विधानसभा मार्ग
लखनऊ – 1
फोन :– 0522–2200187
फैक्स :– 0522–2612437

Email-
bjpkamaljyoti@gmail.com

पत्रिका में प्रकाशित आलेखों से सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं

मुद्रक

नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र,
राजेन्द्र नगर, लखनऊ–4

www.up.bjp.org
bjpkamaljyoti
Vartman Kamaljyoti
@bjpkamaljyoti

नवसम्वतसर व रामनवमी की हार्दिक शुभकामनायें

सम्पादकीय

यूपी उत्कर्ष के आठ वर्ष

पूरे देश में आज उत्तर प्रदेश की साख बढ़ी है। अनेक प्रदेश उत्तर प्रदेश का अनुकरण कर रहे हैं। कानून व्यवस्था आर्थिक स्थिति, कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, सभी क्षेत्रों में अतुलनीय प्रगति हुई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने द्वितीय कार्यकाल के तीन वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। उन्होंने 25 मार्च 2022 को द्वितीय बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस अवसर पर उन्होंने शपथ लेते हुए कहा था कि "मैं आदित्यनाथ योगी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।"

योगी आदित्यनाथ अपनी इस शपथ का किस प्रकार हृदय से पालन कर रहे हैं, यह सर्वविदित है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में लगभग साढ़े तीन दशक के पश्चात किसी राजनीतिक दल को पुनः सत्ता में लाने वाले योगी आदित्यनाथ प्रथम राजनेता हैं। उन्हें अपने मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में अनेक समस्याओं से जूझना पड़ा। उन पर अनेक आरोप लगे। उन पर बुल्डोजर से लोगों के मकान तोड़ने के आरोप लगे। महाकुंभ का सफल आयोजन इस बात का प्रमाण है। महाकुंभ से पूर्व प्रयागराज के ऐतिहासिक मंदिरों का जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण किया गया। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पर्यटन विभाग, स्मार्ट सिटी एवं प्रयागराज विकास प्राधिकरण मिलकर यह कार्य संपन्न किया। मेला प्रशासन ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आस्था एवं सुविधा को प्राथमिकता दी। महाकुंभ मेले के दृष्टिगत प्रदेश को हरभरा बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके अतिरिक्त स्वच्छता पर विशेष बल दिया गया। यातायात सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया। योगी आदित्यनाथ के परिश्रम का परिणाम है कि इस मेले में 66 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान कर पुण्य अर्जित किया। राज्य में गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना प्रारम्भ की गई है, जिसके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। योगी सरकार ने कृषि क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान दिया है। प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए परम्परागत खेती विकास योजना चलाई जा रही है। खेतों को पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश निःशुल्क बोरिंग योजना तथा उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना संचालित की जा रही है। इनके अतिरिक्त बीज ग्राम योजना के अंतर्गत किसानों को धान एवं गेहूं के बीज पर विशेष अनुदान दिया जा रहा है। पारदर्शी किसान सेवा योजना के अंतर्गत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को समुचित उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है। किसानों को ऋण के बोझ से मुक्त करने के लिए किसान ऋण मोचन योजना प्रारम्भ की गई। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

प्रदेश में अनाथ बच्चों को शरण देने के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारम्भ की गई। महिला सशक्तिकरण के लिए भी सरकार अनेक योजनाएं चला रही है।

उत्तर प्रदेश ने 'एक जनपद–एक योजना' को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उत्तर प्रदेश सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना करने वाला उत्तर भारत का प्रथम राज्य है। उत्तर प्रदेश ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 101 करोड़ से अधिक मानव दिवस सृजित कर डेढ़ करोड़ श्रमिकों को रोजगार दिया। उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य है।

देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज अपनी शासन व्यवस्था के कारण ''एक भारत, श्रेष्ठ भारत'' को मूर्तरूप देने में अपनी महती भूमिका निभा रहा है।

हार्दिक बधाई, शुभकामनायें।

कल के लिए "जल" बचाने की जरूरत : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर जल संरक्षण और सतत विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाने की जरूरत पर जोर दिया और भारत में जल सुरक्षा के लिए चल रहे प्रयासों को उजागर किया। हर साल 22 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व जल दिवस वर्ष 1993 से शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य ताजे पानी के महत्व को उजागर करना और सतत विकास लक्ष्य 6 को पूरा करना है, जिसका लक्ष्य 2030 तक सभी को पानी और स्वच्छता तक पहुंच दिलाना है। इस साल की– 'ग्लेशियर संरक्षण' है।

जल जीवन का आधार और दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन

मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "विश्व जल दिवस पर हम जल संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के अपने संकल्प को दोहराते हैं। जल ही जीवन का आधार है, इसलिए इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना जरूरी है।" एक वीडियो संदेश में पीएम ने भारत में जल संरक्षण की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "जल जीवन का आधार और दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण को हमेशा प्राथमिकता दी है। वेदों और पुराणों में भी जलाशय, बांध और तालाब बनाने को मानव का परम कर्तव्य बताया गया है।"

प्रधानमंत्री मोदी ने जल संकट को देश के विकास के लिए भी खतरा बताया। उन्होंने जल जीवन मिशन का उल्लेख करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता, प्रबंधन और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "गांवों में जल स्रोतों के संरक्षण के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। हो सकता है कि जहां आप रहते हैं, वहां पानी की कोई कमी न हो, लेकिन हमें उन लाखों लोगों को याद रखना चाहिए, जो पानी की कमी का सामना कर रहे हैं।"

प्रधानमंत्री ने नदियों के संरक्षण पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि नदियों की रक्षा और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए महाकुंभ जैसे आयोजनों से प्रेरणा लेकर नदी उत्सवों को नया अर्थ देना चाहिए। इससे नई पीढ़ी को जल की महत्ता का एहसास होगा और वे स्वच्छता और संरक्षण के प्रति जागरूक होंगे।

सरकार आतंकवाद को नहीं सह सकती है : शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में गृह विभाग पर हुई चर्चा का जवाब दिया। गृह मंत्री ने चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कांग्रेस सांसद पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने पैदल यात्रा निकाली और अपने कार्यकर्ताओं के साथ कश्मीर में बर्फ की होली खेली और कहा कि दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। लेकिन, हम तो आतंकवादी देखते ही सीधा दो आंखों के बीच में गोली मारते हैं।

गृह मंत्री अमित शाह ने घाटी का जिक्र करते हुए कहा कि पहले कश्मीर में आए दिन पड़ोसी देश से आतंकवादी घुसकर बम धमाके करते थे। एक भी त्योहार ऐसा नहीं होता था, जो चिंता के बगैर जाता था। इसके बाद भी केंद्र सरकार का रवैया लचीला होता था, चुप्पी साध जाते थे, बोलने में डर लगता था, वोट बैंक का भी डर था। पीएम मोदी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई गई। हमारे आने के बाद जब उरी और पुलवामा पर हमले हुए, तो हमने 10 दिन में ही पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके मुंहतोड़ जवाब दिया। पूरी दुनिया में दो ही देश ऐसे थे, जो अपनी सीमा और सेना के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। इजरायल और अमेरिका। इन दोनों देशों की लिस्ट में महान भारत का नाम नरेंद्र मोदी ने जोड़ा और वहीं से शुरू हुई आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति।

षाह ने कहा कि हिसाब मांगते हैं कि क्या हुआ 370 हटाने का परिणाम। साहब, हिसाब तो उनको दिया जाता है, नजारा तो उनको दिखाया जाता है, जिनकी नजरें साफ हों। जो काला चश्मा पहनकर, आंखें मूंदकर बैठे हैं, उनको विकास नहीं दिखा सकते हैं। पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली खेली और कहा कि दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, जिनकी नजर में आतंकवादी है, तो आपको सपने में भी आएगा और आपको कश्मीर में भी दिखाई पड़ेगा। हम तो आतंकवादी देखते ही सीधा दो आंखों के बीच में गोली मारते हैं। हमारी सरकार न आतंकवाद को सह सकती है और न ही आतंकवादियों को।

पिछली सरकारों के शासन में जम्मू कश्मीर में 33 साल से सिनेमाघर नहीं खुले थे, हमारे समय में खुले। ताजिया के जुलूस को अनुमति नहीं थी, हमारे समय में दी गई। जी–20 के दौरान दुनियाभर के डिप्लोमेट शांति से जम्मू कश्मीर गए और वहां का खाना, संस्कृति, खूबसूरती का आनंद उठाया।

गृह मंत्री ने कहा कि 10 साल पहले जम्मूकाष्मीर में आतंकवादियों का महिमामंडन होता था, जनाजों का जुलूस निकाला जाता था। हमारे समय में भी आतंकवादी मारे गए, ज्यादा मारे गए, लेकिन किसी के जनाजे का जुलूस नहीं निकाला गया। जो आतंकवादी जहां मारा जाता है, वहीं दफना दिया जाता है। कई वर्षों से कश्मीर की तिजोरी खाली थी। 2015 में नरेंद्र मोदी ने 80 हजार करोड़ रुपए की 63 परियोजनाओं की शुरुआत की। कुछ लोग मेरे खर्च का हिसाब पूछ रहे थे। अरे भाई, थोड़ा कम हुआ होगा, हमने रखने की हिम्मत तो की, आपके समय में तो खर्च का प्रोविजन ही नहीं था। 80 हजार करोड़ रुपए में से 51 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और 63 में से 53 परियोजनाएं क्रियान्वित हो चुकी हैं।

सेवा, सुशासन, सुराज के आठ साल

डबल इंजन की मोदी–योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में आठ साल बेमिशाल हो गया है। निरन्तर बढ़ती अर्थव्यवस्था, चुस्त–दुरूस्त कानून व्यवस्था, सांस्कृतिक आध्यात्मिक उचाईयों को छूता उ0प्र0 देश का मॉडल बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुशासन व सुदृढ़ कानून व्यवस्था की बदौलत एक तरफ उत्तर प्रदेश को जहां सर्वोत्तम प्रदेश बना डाला, वहीं आठ वर्ष में 204 करोड़ से अधिक पौधरोपण से इसे 'हरित प्रदेश' के रूप में भी समृद्ध कर दिया। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के मुताबिक यूपी के वनावरण व वनाच्छादन में 559.19 वर्गकिमी की वृद्धि हुई है। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ जनअभियान –2024 के तहत यूपी में 36.80 करोड़ पौधरोपण हुए। सीएम योगी के नेतृत्व में वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग ने कई बड़े–बड़े कार्य भी किए। वन विभाग में पारदर्शिता के आधार पर युवाओं को नियुक्ति दी गई। यूपी में पहली बार कार्बन क्रेडिट के जरिये किसानों की आय में वृद्धि हुई। 25 नवम्बर 2024 से लखनऊ से पलिया तक योगी सरकार ने हवाई सेवा भी शुरू की। उत्तर प्रदेश में सारस की संख्या में भी वृद्धि हुई।

उत्तर प्रदेश की नदियों में तैरती डॉल्फिन –

योगी सरकार के प्रयास का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश की नदियों में सर्वाधिक डॉल्फिन पाई गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सातवीं बैठक में रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक देश में नदी डॉल्फिन की कुल संख्या 6,327 रही। देश के आठ राज्यों की 28 नदियों के सर्वेक्षण में सर्वाधिक संख्या (2397 डॉल्फिन) के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। अन्य राज्य यूपी से पीछे हैं। योगी सरकार ने 17 अक्टूबर 2023 को गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया था।

बढ़ता अरण्य क्षेत्र –

योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 204 करोड़ से अधिक पौधरोपण किया गया। विगत वर्ष 36.80 करोड़ पौधरोपण कर उत्तर प्रदेश ने नया रिकॉर्ड स्थापित किया। भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश का वनाच्छादन 559.19 वर्ग किमी. बढ़ा है। छत्तीसगढ़ को छोड़कर सभी राज्य उत्तर प्रदेश से पीछे हैं।

वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग की प्रमुख उपलब्धियां –

आठ वर्ष में विभाग के अंतर्गत लगभग ढाई हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। अभी हाल में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 सितंबर को 647 वन रक्षकों–वन्य जीव रक्षकों और 22 नवंबर को 701 वन दारोगा को प्रदान किया था नियुक्ति पत्र।

दुधवा टाइगर रिजर्व/दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में ईको पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए 25 नवम्बर 2024 को लखनऊ से पलिया तक हवाई सेवा का किया गया शुभारंभ।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा छह सितंबर 2024 को गोरखपुर के कैम्पियरगंज में एशिया के प्रथम नवनिर्मित जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया। नव निर्मित जटायु / राजगिद्ध के संरक्षण व संवर्धन केंद्र में कुल छह राजगिद्धों (नर

एवं मादा) को लाया जा चुका है।

पेड़ लगाओ–पेड़ बचाओ जन अभियान, 2024 के अंतर्गत वर्ष में 36.80 करोड़ पौधरोपण किए गए। 20 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ, प्रयागराज व गोरखपुर में पौधरोपण किया। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 223 महत्वपूर्ण वेटलैण्ड्स के जलागम क्षेत्र में 'वेटलैण्ड संरक्षण वन' की स्थापना की गई।

प्रदेश में 948 विरासत वृक्ष वाटिका का निर्माण किया गया। इसके अलावा मित्र वन, मियावाकी वन, सौमित्र वन, शक्ति वन आयुष वन, पंचवटी, नवग्रह वाटिका की स्थापना की गई। गंगा, यमुना, सरयू, हिंडन, गोमती सहित विभिन्न नदियों के जलागम क्षेत्र में 'पवित्र धारा वृक्षारोपण' योजना के तहत लगभग 3.72 करोड़ पौधरोपण किया गया।

किसानों की निजी भूमि पर खड़े वृक्षों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जुलाई 2024 को कार्बन क्रेडिट का भुगतान किया। निजी वृक्षों के लिए कार्बन क्रेडिट का भुगतान करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है।

ग्रीष्मकालीन गणना 2024 के अनुसार प्रदेश में राज्य पक्षी सारस की संख्या बढ़कर 19994 हो गई। 2023 में यह संख्या 19522 व 2022 में 19188 थी।

योगी सरकार ने लगाए 204 करोड़ से अधिक पौधे

वर्ष पौधरोपण

2017	–	18 5.72 करोड़
2018	–	19 11.77 करोड़
2019	–	20 22.60 करोड़
2020	–	21 25.87 करोड़
2021	–	22 30.53 करोड़
2022	–	23 35.49 करोड़
2023	–	24 36.16 करोड़
2024	–	25 36.80 करोड़

पेड़ लगाओ–पेड़ बचाओ जनअभियान 2024 की प्रमुख उपलब्धि पौधरोपण– 36.80 करोड़

सर्वाधिक पौधरोपण वाले जनपद– सोनभद्र प्रथम (1.53 करोड़), झांसी द्वितीय (97 लाख), लखीमपुर खीरी तृतीय (95 लाख), जालौन चतुर्थ (94 लाख) व मीरजापुर (93 लाख) पांचवें स्थान पर रहा।

सर्वाधिक पौधरोपण वाले विभाग– ग्राम्य विकास विभाग (13.54 करोड़), वन विभाग (12.64 करोड़), कृषि विभाग (2.89 करोड़), उद्यान विभाग (1.61 करोड़), पंचायती राज विभाग (1.18 करोड़)

सर्वाधिक लगाए गए पौध– शीशम (4 करोड़ 33 लाख, 38723), सागौन (4.33 करोड़ से अधिक), जामुन (2.19 करोड़ से अधिक), अर्जुन (1.67 करोड़), आंवला (95 लाख से अधिक)।

उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने भारत की सांस्कृतिक विरासत का विश्व से कराया परिचय : योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'भारत रत्न' शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जयंती पर शुक्रवार को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि उनकी संगीत साधना वंदनीय है। सीएम योगी के साथ ही गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने भी उत्साद को नमन किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपने वादन के जरिए उन्होंने भारत की सांस्कृति से विश्व को रूबरू कराया। उन्होंने लिखा, "सुप्रसिद्ध शहनाई वादक, 'भारत रत्न' उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई वादन से भारत की सांस्कृतिक विरासत के विराट स्वरूप का विश्व से परिचय कराया, उनकी संगीत साधना वंदनीय है।

खां का जन्म बिहार में हुआ था, मगर उन्हें बनारस से अगाध प्रेम था : अभिनेता और गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने एक्स पर उस्ताद को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, "भारत रत्न से अलंकृत, भारत के प्रख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब जी की जयंती पर उन्हें कोटि–कोटि नमन।" उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार में हुआ था, मगर उन्हें बनारस से अगाध प्रेम था। एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा था, "अगर किसी को सुरीला बनना है तो बनारस चला आए और गंगा जी के किनारे बैठ जाए, क्योंकि बनारस के नाम में "रस" आता है।"

बिस्मिल्लाह खां ने गंगा-जमुनी तहजीब को दिया बढ़ावा : बिस्मिल्लाह खां ने कहा था, "चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर हो या बालाजी मंदिर या फिर गंगा घाट, यहां शहनाई बजाने में एक अलग ही सुकून मिलता है।" बिस्मिल्लाह खां ने गंगा–जमुनी तहजीब को भी बढ़ावा दिया। वह बाबा विश्वनाथ मंदिर में जाकर तो शहनाई बजाते ही थे। साथ ही गंगा किनारे बैठकर घंटों तक रियाज भी करते थे। त्योहार कोई भी हो, खान साहब की शहनाई के बगैर वह अधूरा ही था। उनके लिए संगीत ही उनका धर्म था।

उस्ताद को भारत के चारों सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों से किया गया है सम्मानित

उन्होंने यूएसए, कनाडा, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, वेस्ट अफ्रीका जैसे देशों में शहनाई बजाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत के चारों सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें पद्म श्री (1961), पद्म भूषण (1968), पद्म विभूषण (1980) और 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया था।

शिक्षा में बदलाव की ओर बढ़ता प्रदेश

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने आठ साल के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव किए हैं। 2017 में सत्ता संभालने के बाद से प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक को गुणवत्तापरक बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए। स्कूलों की बदहाल स्थिति को सुधारने से लेकर नए विश्वविद्यालयों की स्थापना तक, सरकार ने शिक्षा को सशक्त और समावेशी बनाने का संकल्प पूरा किया। योगी सरकार के 8 सालों में शिक्षा सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि एक मिशन बन गई है। ऑपरेशन कायाकल्प से लेकर विश्वविद्यालयों की स्थापना तक, हर कदम बच्चों और युवाओं को वैश्विक मंच पर तैयार करने की दिशा में उठाया गया है। यह बदलाव न केवल शिक्षा का स्तर ऊंचा कर रहा

है,बल्कि उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है।

ऑपरेशन कायाकल्प से मिली स्कूलों को न पहचान

बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के अनुसार 2017 में बच्चों के पास यूनिफॉर्म, जूते और बैग तक नहीं थे। योगी सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प के तहत बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का कायाकल्प किया। उन्हें आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा गया। इसका नतीजा सबके सामने है। आज 1.91 करोड़ बच्चों को दो यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते, बैग, साथ ही स्कूलों में स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, टॉयलेट और पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। हर साल अभिभावकों के खातों में सीधे धनराशि भेजी जा रही है।

शिक्षा का किया गया आधुनिकीकरण

पीएम श्री योजना के तहत 1,565 विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। 6,481 स्कूलों को नए सिरे से बनाया जा रहा है, ताकि बच्चों को बेहतर माहौल मिले। 57 कंपोजिट विद्यालयों के लिए बजट स्वीकृत किया गया है, जो प्री–प्राइमरी से 12वीं तक एक ही कैंपस में शिक्षा देंगे।

बालिकाओं और ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस

कस्तूरबा गांधी विद्यालय के तहत गरीब बालिकाओं के लिए 8वीं तक सीमित इन स्कूलों को 12वीं तक विस्तारित किया गया। वंटागिया गांवों में शिक्षा के प्रसार के लिए 22 प्राथमिक और 11 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण, ग्रामीण बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ा गया। अटल आवासीय विद्यालयों के अंतर्गत इंटीग्रेटेड कैंपस के साथ बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर प्रदान किया गया।

उच्च शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण में क्रांति

सहारनपुर, अलीगढ़, आजमगढ़, मीरजापुर, देवीपाटन और मुरादाबाद में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें से तीन शुरू हो चुके हैं। 150 आईटीआई में एआई, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन और रोबोटिक्स जैसे न्यू एज कोर्स शुरू किये गये। साथ ही 62 नए आईटीआई का भी निर्माण किया गया। यही नहीं, संस्कृत शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया, जिसके अंतर्गत पहली बार पूर्वा से आचार्य स्तर तक छात्रवृत्ति शुरू की गयी, विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान की गयी।

युवाओं का सशक्तिकरण, बांटे स्मार्टफोन

डिजिटल क्रांति के तहत योगी सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने का लक्ष्य रखा और 50 लाख को वितरित भी कर दिया। युवाओं में अनुशासन और देशभक्ति के लिए अकादमी और स्कूलों का निर्माण तेज गति से किया जा रहा है। ब्लॉक और न्याय पंचायत स्तर तक कंपोजिट स्कूलों का विस्तार किया गया है और एक नया एजुकेशन हब बनाने की तैयारी है।

उद्यम प्रदेश-सर्वोत्तम प्रदेश

योगी सरकार के 8 साल बेमिसाल

यूपी सरकार ने निवेश आकर्षित करने के लिए 2018 में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) का आयोजन किया. फरवरी 2023 में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट–2023 ने निवेश का नया अध्याय लिखा।

उत्तर प्रदेश में बीते आठ सालों में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। बीजेपी का दावा जो राज्य 2017 तक 'बीमारू' माना जाता था, वह अब देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने औद्योगिक निवेश, रोजगार और कारोबारी सुगमता को प्राथमिकता दी, जिसका असर यह हुआ कि यूपी अब 'उद्यम प्रदेश' बन चुका है।

योगी सरकार के प्रयासों से प्रदेश में अब तक 45 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश को धरातल पर उतार दिया गया है। इससे अब तक 60 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिल चुका है। सरकार की नीतियों का ही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था दोगुनी हो चुकी है और प्रदेश जल्द ही 30 लाख करोड़ रुपये के जीडीपी आंकड़े को पार कर लेगा।

नीतियों से उद्योगों को बढ़ावा

प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने 33 सेक्टोरल पॉलिसी बनाई। 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को प्राथमिकता दी गई और 'निवेश मित्र' पोर्टल शुरू किया गया, जिससे अब 43 विभागों की 487 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता रैंकिंग में यूपी 2017 में 14वें स्थान पर था, जो 2022 में दूसरे स्थान पर पहुंच गया।

उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश आकर्षित करने के लिए 2018 में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) का आयोजन किया। फरवरी 2023 में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट–2023 ने निवेश का नया अध्याय लिखा। निवेश को धरातल पर उतारने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (GBC) भी आयोजित की गई, जिसके तहत करोड़ों रुपये की परियोजनाएं लागू की गईं। प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर में 90 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। निर्यात 86 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसमें एक जिला–एक उत्पाद (ODOP) योजना का बड़ा योगदान रहा।

यूपी को बनाया निवेश हब

- ➢ डिफेंस कॉरिडोर, मेडिकल और फार्मा सेक्टर में 63,475 करोड़ रुपये के निवेश से स्वास्थ्य सेवाओं और विनिर्माण में तेजी आई है।
- ➢ एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डों और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार से यूपी निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थान बन गया है।
- ➢ यूपी सरकार स्टार्टअप, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, एआई, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन को बढ़ावा दे रही है।
- ➢ लखनऊ–हरदोई में टेक्सटाइल पार्क, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, कानपुर में मेगा लेदर क्लस्टर और कन्नौज में परफ्यूम पार्क जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है।
- ➢ इन्वेस्ट यूपी के जरिए निवेश को ट्रैक किया जा रहा है और लैंड पूलिंग व अलॉटमेंट जैसी योजनाओं से निवेशकों की दिक्कतें कम हो रही हैं।

औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई

- ➨ 06 औद्योगिक गलियारे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और 06 गलियारे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर विकसित हो रहे हैं।
- ➨ 47 साल बाद यूपी को बीडा के रूप में नया औद्योगिक शहर मिल रहा है।
- ➨ बुंदेलखंड में ड्रग व फार्मा पार्क की स्थापना को तेज किया गया है।

छोटे उद्यमियों को बड़ी राहत

- ➤ मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना में पंजीकृत उद्यमियों के लिए 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जा रहा है।
- ➤ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत अब तक 16 हजार मामलों में ऋण स्वीकृत हुए हैं और 6 हजार मामलों में ऋण वितरित किया गया है।
- ➤ अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत भी की गई है।

योगी सरकार की इन योजनाओं और सुधारों से यूपी की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, युवाओं को रोजगार मिला है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार ऊंचाइयों को छू रही है। उत्तर प्रदेश अब एक 'ब्रेकथ्रू' प्रदेश के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है।

नव सम्वत् पर संस्कृति का सादर वन्दन!

डॉ. सौरभ मालवीय

नवरात्र हवन के झोंके, सुरभित करते जनमन को।
है शक्तिपूत भारत, अब कुचलो आतंकी फन को।।
नव सम्वत् पर संस्कृति का, सादर वन्दन करते हैं।
हो अमित ख्याति भारत की, हम अभिनन्दन करते हैं।।

30 मार्च से विक्रम संवत 2082 प्रारम्भ हो गया है। विक्रम संवत को नव संवत्सर भी कहा जाता है। संवत्सर पांच प्रकार के होते हैं, जिनमें सौर, चन्द्र, नक्षत्र, सावन और अधिमास सम्मिलित है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ एवं मीन नामक बारह राशियां सूर्य वर्ष के माह हैं। सूर्य का वर्ष 365 दिन का होता है। इसका प्रारंभ सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने से होता है। **चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ और फाल्गुन**

चन्द्र वर्ष के महीने हैं। चन्द्र वर्ष 355 दिन का होता है। इस प्रकार इन दोनों वर्षों में दस दिन का अंतर हो जाता है। चन्द्र माह के बढ़े हुए दिनों को ही अधिमास या मलमास कहा जाता है। नक्षत्र माह 27 दिन का होता है, जिन्हें अश्विन नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, घनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र, रेवती नक्षत्र कहा जाता है। सावन वर्ष में 360 दिन होते हैं। इसका एक माह 30 दिन का होता है।

भारतीय संस्कृति में विक्रम संवत का बहुत महत्व है। चैत्र का महीना भारतीय कैलेंडर के हिसाब से वर्ष का प्रथम महीना है। नवीन संवत्सर के संबंध में अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। वैदिक पुराण एवं शास्त्रों के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को आदिशक्ति प्रकट हुई थीं। आदिशक्ति के आदेश पर ब्रह्मा ने सृष्टि की प्रारम्भ की थी। इसीलिए इस दिन को अनादिकाल से नववर्ष के रूप में जाना जाता है। मान्यता यह भी है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। इसी दिन सतयुग का प्रारम्भ हुआ था। मान्यता है कि इसी दिन सम्राट विक्रमादित्य ने अपना राज्य स्थापित किया था। श्रीराम का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। युधिष्ठिर का राज्यभिषेक भी इसी दिन हुआ था। नवरात्र भी इसी दिन से प्रारम्भ होते हैं। इसी तिथि को राजा विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त की थी। विजय को चिर स्थायी बनाने के लिए उन्होंने विक्रम संवत का शुभारंभ किया था, तभी से विक्रम संवत चली आ रही है। इसी दिन से महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, महीने और वर्ष की गणना कर पंचांग की रचना की थी। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ऐतिहासिक महत्व भी है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसी दिन आर्य समाज की स्थापना की थी। इस दिन महर्षि गौतम जयंती मनाई जाती है। इस दिन संघ संस्थापक डॉ. केशवराव बलिराम हेडगेवार का जन्मदिवस भी मनाया जाता है।

सृष्टि की सर्वाधिक उत्कृष्ट काल गणना का श्रीगणेश भारतीय ऋषियों ने अति प्राचीन काल से ही कर दिया था। तदनुसार हमारे सौरमंडल की आयु लगभग चार अरब 32 करोड़ वर्ष हैं। आधुनिक विज्ञान भी, कार्बन डेटिंग और हॉफ लाइफ पीरियड की सहायता से इसे लगभग चार अरब वर्ष पुराना मान रहा है। इतना ही नहीं, श्रीमद्भागवद पुराण, श्री मारकंडेय पुराण और ब्रह्म पुराण के अनुसार अभिशेत् बाराह कल्प चल रहा है और एक कल्प में एक हजार चतुरयुग होते हैं। जिस दिन सृष्टि का प्रारम्भ हुआ, वह आज ही का पवित्र दिन था। इसी कारण मदुराई के परम पावन शक्तिपीठ मीनाक्षी देवी के मंदिर में चैत्र पर्व की परंपरा बन गई।

भारतीय महीनों का नामकरण भी बड़ा रोचक है अर्थात जिस महीने की पूर्णिमा जिस नक्षत्र में पड़ती है, उसी के नाम पर उस महीने का नामकरण किया गया है, उदाहरण के लिए इस महीने की पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र में हैं, इसलिए इसे चैत्र महीने का नाम दिया गया। क्रांति वृंत पर 12 महीने की सीमाएं तय करने के लिए आकाश में 30–30 अंश के 12 भाग किए गए और उनके नाम भी तारा मंडलों की आकृतियों के

आधार पर रखे गए। इस प्रकार बारह राशियां बनीं।
चूंकि सूर्य क्रांति मंडल के ठीक केंद्र में नहीं हैं, अतः कोणों के निकट धरती सूर्य की प्रदक्षिणा 28 दिन में कर लेती है और जब अधिक भाग वाले पक्ष में 32 दिन लगता है। प्रति तीन वर्ष में एक मास अधिक मास कहलाता है।
भारतीय काल गणना इतनी वैज्ञानिक व्यवस्था है कि शताब्दियों तक एक क्षण का भी अंतर नहीं पड़ता, जबकि पश्चिमी काल गणना में वर्ष के 365.2422 दिन को 30 और 31 के हिसाब से 12 महीनों में विभक्त करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक चार वर्ष में फरवरी महीने को लीप ईयर घोषित कर देते हैं। तब भी भी नौ मिनट 11 सेकेंड का समय बच जाता है, तो प्रत्येक चार सौ वर्षों में भी एक दिन बढ़ाना पड़ता है, तब भी पूर्णाकन नहीं हो पाता। अभी कुछ वर्ष पूर्व ही पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु घड़ी को एक सेकेंड स्लो कर दिया गया। फिर भी 22 सेकेंड का समय अधिक चल रहा है। यह पेरिस की वही प्रयोगशाला है, जहां के सीजीएस सिस्टम से संसार भर के सारे मानक तय किए जाते हैं। रोमन कैलेंडर में तो पहले 10 ही महीने होते थे। किंगनुमापाजुलियस ने 355 दिनों का ही वर्ष माना था, जिसे जुलियस सीजर ने 365 दिन घोषित कर दिया और उसी के नाम पर एक महीना जुलाई बनाया गया। उसके एक सौ वर्ष पश्चात किंग अगस्ट्स के नाम पर एक और महीना अगस्ट अर्थात अगस्त भी बढ़ाया गया। चूंकि ये दोनों राजा थे, इसलिए इनके नाम वाले महीनों के दिन 31 ही रखे गए। आज के इस वैज्ञानिक युग में भी यह कितनी हास्यास्पद बात है कि लगातार दो महीने के दिनों की संख्या समान हैं, जबकि अन्य महीनों में ऐसा नहीं है। यही नहीं जिसे हम अंग्रेजी कैलेंडर का नौवां महीना सितम्बर कहते हैं, दसवां महीना अक्टूबर कहते हैं, ग्यारहवां महीना नवम्बर और बारहवां महीना दिसम्बर हैं। इनके शब्दों के अर्थ भी लैटिन भाषा में 7,8,9 और 10 होते हैं। भाषा विज्ञानियों के अनुसार भारतीय काल गणना पूरे विश्व में व्याप्त थी और सचमुच सितम्बर का अर्थ सप्ताम्बर था, आकाश का सातवां भाग, उसी प्रकार अक्टूबर अष्टाम्बर, नवम्बर तो नवमअम्बर और दिसम्बर दशाम्बर है।
वर्ष 1608 में एक संवैधानिक परिवर्तन द्वारा एक जनवरी को नववर्ष घोषित किया गया। जेनदअवेस्ता के अनुसार धरती की आयु लगभग 12 हजार वर्ष है। चीनी कैलेंडर लगभग एक करोड़ वर्ष पुराना मानता है। चालडियन कैलेंडर धरती को लगभग दो करोड़ 15 लाख वर्ष पुराना मानता है। फीनीसयन इसे लगभग 30 हजार वर्ष की बताते हैं। सीसरो के अनुसार यह लगभग चार लाख 80 हजार वर्ष पुरानी है। सूर्य सिद्धांत और सिद्धांत शिरोमाणि आदि ग्रंथों में चैत्रशुक्ल प्रतिपदा रविवार का दिन ही सृष्टि का प्रथम दिन माना गया है। संस्कृत के होरा शब्द से ही, अंग्रेजी का आवर (Hour) शब्द बना है। इस प्रकार यह सिद्ध हो रहा है कि वर्ष प्रतिपदा ही नव वर्ष का प्रथम दिन है। एक जनवरी को नववर्ष मनाने वाले दोहरी भूल के शिकार होते हैं, क्योंकि भारत में जब 31 दिसम्बर की रात को 12 बजता है, तो ब्रिटेन में सायंकाल होता है, जो कि नववर्ष की पहली सुबह हो ही नहीं सकती। और जब उनका एक जनवरी का सूर्योदय होता है, तो यहां के Happy New Year मनाने वाले रात्रि भर जागने कारण सो रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए सवेरे नहा धोकर भगवान सूर्य की पूजा करना तो अत्यंत दुष्कर कार्य है। परन्तु भारतीय नववर्ष में वातावरण अत्यंत मनोहारी रहता है। केवल मनुष्य ही नहीं, अपितु जड़ चेतना नर–नाग यक्ष रक्ष किन्नर–गंधर्व, पशु–पक्षी लता, पादप, नदी नद, देवी, देव, मानव से समष्टि तक सब प्रसन्न होकर उस परम शक्ति के स्वागत मंज सन्नध रहते हैं।
दिवस सुनहले, रात रूपहली, उषा सांझ की लाली छन–छन कर पत्तों में बनती हुई चांदनी जाली कितनी मनोहारी लगती है। शीतल मंद सुगंध पवन वातावरण में हवन की सुरभि कर देते हैं। ऐसे ही शुभ वातावरण में अखिल लोकनायक श्रीराम का अवतार होता है।
उल्लेखनीय है कि ज्योतिष विद्या में ग्रह, ऋतु, मास, तिथि एवं पक्ष आदि की गणना भी चैत्र प्रतिपदा से ही की जाती है। मान्यता है कि नव संवत्सर के दिन नीम की कोमल पत्तियों और पुष्पों का मिश्रण बनाकर उसमें काली मिर्च, नमक, हींग, मिश्री, जीरा और अजवाइन मिलाकर उसका सेवन करने से शरीर स्वस्थ रहता है। इस दिन आंवले का सेवन भी बहुत लाभदायद बताया गया है। माना जाता है कि आंवला नवमीं को जगत पिता ने सृष्टि पर पहला सृजन पौधे के रूप में किया था। यह पौधा आंवले का था। इस तिथि को पवित्र माना जाता है। इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा–अर्चना होती है।
निसंदेह, जब भारतीय नववर्ष का प्रारंभ होता है, तो चहुंओर प्रकृति चहक उठती है। भारत की बात ही निराली है।
कवि श्री जयशंकर प्रसाद के शब्दों में–

अरुण यह मधुमय देश हमारा
जहां पहुंच अनजान क्षितिज को
मिलता एक सहारा
अरुण यह मधुमय देश हमारा

इसमें संदेह नहीं कि आज हमारे दैनिक जीवन में अंग्रेजी कैलेंडर का बहुत प्रचलन है, परन्तु हमारे तीज–त्यौहार, व्रत, उपवास, रामनवमी जन्माष्टमी, गृह प्रवेश, विवाह तथा अन्य शुभ कार्यों के शुभमुहूर्त आदि सभी आयोजन भारतीय कैलेंडर अर्थात हिन्दू पंचांग के अनुसार ही देखे जाते हैं।
आइए इस शुभ अवसर पर हम भारत को पुनः जगतगुरु के पद पर आसीन करने में कृत संकल्प हों।

जनप्रतिनिधित्व लोकतंत्र की आत्मा है

लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर खासी बहस चल निकली है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा है कि, "परिसीमन जनसंख्या के आधार पर ही नहीं किया जाना चाहिए, इससे दक्षिण के राज्यों को नुकसान होगा।" केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि, "परिसीमन प्रक्रिया से दक्षिणी राज्यों को नुकसान नहीं होगा। सरकार किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होने देगी।" उन्होंने सीटों में वृद्धि होने पर उचित हिस्सा देने का वादा किया है। फिर भी वाक् युद्ध जारी है। परिसीमन संवैधानिक उत्तरदायित्व है। संविधान (अनुच्छेद 82) में कहा गया है कि, "प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों को लोक सभा में स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे।" संविधान में जनसंख्या को ही सीटों के निर्धारण का मुख्य आधार बताया गया है। इसी लिए प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन का प्राविधान है। परिसीमन का कार्य जनसँख्या परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को पुनः समायोजित करना व विभिन्न क्षेत्रों के बीच सीटों का समान वितरण सुनिश्चित करना है। तत्सम्बंधी कानून के अनुसार परिसीमन कार्य के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है। अब तक चार बार इस आयोग का गठन हो चुका है। 1976 में संशोधन अधिनियम द्वारा सन 2000 तक लोक सभा सीट आवंटन और निर्वाचन क्षेत्र विभाजन को 1971 के स्तर पर स्थिर कर दिया था।

लोक सभा की राज्यवार संरचना में परिवर्तन लाने वाला परिसीमन वर्ष 1976 में हुआ था। यह 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था। फिर 2001 में इसे 2026 तक 25 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। 2003 में निर्वाचन क्षेत्र की संख्या में परिवर्तन किए बिना 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की कार्रवाई चली थी। कम आबादी वाले राज्यों को जनसंख्या आधारित परिसीमन प्रक्रिया से अलग किया गया। केवल जनसंख्या आधारित परिसीमन पर्याप्त नहीं है।

भौगोलिक कारक भी महत्वपूर्ण हैं। देश के कई राज्यों में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का आकार बहुत बड़ा है। कोई पूर्णकालिक सांसद भी अपने क्षेत्र का दौरा पूरे साल में भी नहीं कर सकता। परिसीमन का कार्य केवल जनसँख्या के अनुसार सीटों का पुनः संयोजन ही नहीं है। कायदे से यह देखा जाना चाहिए कि क्या लोकसभा की सीटें घटाने या बढ़ाने से संसदीय कार्यवाही की गुणवत्ता बढ़ेगी? क्या इस परिसीमन से देश की विकास दर बढ़ेगी? क्या परिसीमन की कसरत से जनप्रतिनिधि का कार्य सरल होगा? जनसंख्या वृद्धि राष्ट्रीय समस्या है। संतुलित जनसंख्या से राष्ट्रीय क्षमता पर अच्छा असर पड़ता है। सरकारें जनसंख्या नियंत्रण पर अपने तरीकों से काम करती हैं। जनसंख्या का नियमन राष्ट्रीय विकास को गति देता है। दुर्भाग्य से जनसंख्या नियंत्रण जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम को 1975 के आपातकाल में जबरदस्ती नसबंदी के कारण धक्का लगा। जनसँख्या नियंत्रण कार्यक्रम बदनाम हुआ। विकास की सारी योजनाएं भारी जनसंख्या के दबाव के कारण सफल होते नहीं दिखाई पड़तीं। देश में उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थाएं बढ़ी हैं। मेडिकल कॉलेज भी बढ़े हैं। रेलें और बसें भी बढ़ी हैं। लेकिन बढ़ती जनसंख्या के कारण सब जगह घोर अव्यवस्था है। लोक सभा की सीटें बढ़ा या घटा देने से व्यवस्था में किसी बड़े परिवर्तन की उम्मीद नहीं की जा सकती। बेशक

आदर्श प्रतिनिधित्व समय की मांग है इसके लिए जनसंख्या के साथ ही विकास सूचकांक, अर्थव्यवस्था को गति देने वाले समूह और शासन की गुणवत्ता भी विचारणीय विषय हो सकते हैं।

जनसंख्या ही जनप्रतिनिधित्व का आधार है। यह सब जानते हुए भी जनसँख्या आधारित परिसीमन पर स्टालिन हमलावर हैं, लेकिन उन्होंने भी जनसंख्या आधारित परिसीमन की ही मांग की है। उनके अनुसार 1971 की जनगणना का आंकड़ा ही मार्गदर्शी होना चाहिए। उनकी सारी चिंताएं राजनीतिक हैं। उनका गुस्सा भी राजनीतिक है और मांगे भी। एक विचार यह भी है कि 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या स्थिर करने का उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण प्रोत्साहन था। जनसंख्या आधारित परिसीमन संविधान की अपेक्षा है। लेकिन अधिक जनसंख्या हमेशा भार ही नहीं होती। जनशक्ति राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ाती है। बड़ी जनसंख्या की श्रम शक्ति को उपयोग में लाकर नए नतीजे पाए जा सकते हैं। आदर्श प्रतिनिधित्व समय की मांग है इसके लिए जनसंख्या के साथ ही विकास सूचकांक, अर्थव्यवस्था को गति देने वाले समूह और शासन की गुणवत्ता भी विचारणीय विषय हो सकते हैं। विशिष्ट संस्कृति वाले क्षेत्र भी आधार बनाए जा सकते हैं।

जनप्रतिनिधित्व लोकतंत्र की आत्मा है। लगभग 15 से 20 लाख मतदाता लोकसभा के लिए अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। वे विधायक सांसद होकर विधि निर्माण में हिस्सा लेते हैं। वे सरकार बनाते है, सरकार बनते हैं और जिम्मेदार विपक्ष बनते हैं। वे आम जनता के मध्य सेतु का काम करते हैं। लोकसभा में सीटों का आवंटन राज्य के मतदाताओं की संख्या के आधार पर होना चाहिए। वंचित वर्ग तमाम अभाव में जीवन यापन करते हैं। संवैधानिक प्राविधानों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का आवंटन भी परिसीमन आयोग की जिम्मेदारी है। जनसँख्या में बदलाव का प्रभाव पड़ता है। परिसीमन आयोग संवैधानिक संस्था है। आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह निर्वाचन आयोग के साथ काम करता है। बहुत संभव है कि कुछ दलों को आयोग का निर्णय कम अच्छा लगे। बावजूद इसके लोकसभा के लिए सीटों का समायोजन महत्वपूर्ण है। ऐसे मामलों में राजनीतिक बयानबाजी उचित नहीं होती। परिसीमन गंभीर संवैधानिक जिम्मेदारी है। यहां इस या उस राज्य में सीटों का घटना बढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है। किसी दल या समूह की चुनाव सम्भावना भी देखना नहीं है। महत्वपूर्ण बात है राष्ट्रीय एकता और अखण्डता। लेकिन यह सब जानते हुए भी उत्तर दक्षिण की अलगाववादी बयानबाजी जारी है। संघीय ढांचे को खतरा बताया जा रहा है। राष्ट्र को नुकसान पहुँचाने वाली बातें की जा रही हैं।

1913 से अमेरिकी हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सीटों की संख्या 435 तक सीमित रही है। अमेरिका में भी जनसंख्या वृद्धि हुई। 1911 में जनसंख्या 9.4 करोड़ थी। 2023 में 33.4 करोड़ हो गई। अमेरिका में भी प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन होता है। समान अनुपात की विधि से राज्यों के बीच सीटों का समायोजन होता है। वर्ष 2020 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजन हुआ, लेकिन 37 राज्यों की सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अमेरिकी राज्य भारतीय राज्यों से भिन्न हैं। अमेरिका राज्यों के समझौते से बना राष्ट्र राज्य है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। 720 सदस्यों वाली यूरोपीय संघ संसद में सीटों की संख्या को 27 सदस्य देशों के बीच विभजित किया गया है। जनसँख्या बढ़ने पर सीटों की संख्या का अनुपात बढ़ता है। डेनमार्क में 15 सीटें (प्रति सदस्य 4 लाख की औसत आबादी) है, 8.3 करोड़ की आबादी वाले जर्मनी में 96 सीटें (प्रति सदस्य 8.6 लाख की औसत आबादी) है। परिसीमन बिला वजह सिर्फ राजनीतिक कारणों से विवाद में है। परिसीमन सम्बंधी चिंताओं को दूर करने के लिए आम सहमति बनाने के प्रयास होते रहे हैं। इसके लिए संवैधानिक समीक्षा पैनल की स्थापना की जा सकती है। जनसँख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व कारकों के बारे में वैकल्पिक विचार की संभावना पर चिंतन होना चाहिए। जनअपेक्षा है कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष तथ्य और तर्क के आधार पर निश्चित ही श्रेष्ठ नतीजे पर पहुंचेंगे।

संघ विरोधियों को मोदी का उत्तर

मृत्युंजय दीक्षित

अपने जन्मकाल से ही अविचलित रूप से राष्ट्र सेवा करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब अपनी शताब्दी तक पहुंच गया है। माँ भारती और हिन्दू समाज की इस अहर्निश सेवा यात्रा में संघ पर नियमित रूप से राजनैतिक हमले भी होते रहे किन्तु संघ न डरा न डिगा वरन सतत संकल्पवान होकर भारत माँ की सेवा में तत्पर रहा। संभवतः संघ का यह निष्कंप समर्पण ही उसके विरोधियों को भयग्रस्त करता है और उन्हें तर्कहीन बातें कहने को बाध्य करता है।

संघ पर हमले का एक उदहारण महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी के बयान के रूप में सामने आया है। 12 मार्च 2025 को केरल के तिरुअनंतपुरम में गांधीवादी नेता पी गोपीनाथन नायर की प्रतिमा का अनावरण करते हुए तुषार गांधी ने कहा, "राष्ट्र की आत्मा कैंसर से पीड़ित है और संघ परिवार इसे फैला रहा है" । यही नहीं उन्होंने भाजपा और संघ को केरल में प्रवेश करने वाला एक कपटी शत्रु बताया। तुषार ने संघ को जहर भी कहा। इस वक्तव्य के बाद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के कार्यकर्ता केरल में तुषार गांधी से मांफी मांगने व उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके प्रति उत्तर में तुषार गांधी ने कहा कि वह अपनी बातों से पीछे हटने या उनके लिए माफी मांगने में विश्वास नहीं करते। वह संघ के प्रति नफरत से इस सीमा तक भरे हुए हैं कि कहते हैं कि अब हमारा एक साझा दुश्मन है और वह है संघ। भाजपा ने तुषार गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि तुषार गांधी कई वर्षो से महात्मा गांधी के नाम को आर्थिक लाभ के लिए भुनाने का प्रयास कर रहे हैं।

आज महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी संघ को कैंसर बता रहे जबकि स्वयं महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविर में गये थे और अपने अनुभव साझा करते हुए लिखा था कि," कुछ वर्ष पहले जब संघ के संस्थापक जीवित थे आपके शिविर में गया था। वहां पर आपके अनुशासन, अस्पृश्यता का पूर्णरूप से अभाव और कठोर सादगीपूर्ण जीवन देखकर काफी प्रभावित हुआ। सेवा और स्वार्थ त्याग के उच्च आदर्श से प्रेरित कोई भी संगठन दिन प्रतिदिन अधिक शक्तिवान हुए बिना नही रहेगा।"

किन्तु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर केवल तुषार गांधी ही हमला नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे इंडी गठबंधन के नेता किसी न किसी बहाने संघ पर हमलवार रहे है क्योंकि संघ निरंतर हिंदू समाज को एकरस करने के लिए कार्य कर रहा है जिससे इनकी जातिवादी– क्षेत्रवादी– भाषावादी और परिवारवादी राजनीति का भविष्य दांव पर लग गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के पूरे प्रपंच को एक बार में ही ध्वस्त कर दिया है और पूरे विश्व को संघ शक्ति का परिचय दे दिया है। अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन को दिये एक लंबे साक्षात्कार में संघ के समर्पित स्वयंसेवक नरेन्द्र मोदी ने संघ के विरोधियों का मुंह बंद करते हुए संघ के विरुद्ध जो नफरत भरा वातावरण तैयार किया जा रहा था उसे ध्वस्त करने का सार्थक प्रयास किया है। प्रधानमंत्री मोदी का यह पॉडकास्ट पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बिंदु बन चुका है। इस पॉडकास्ट को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने निजी सोशल मीडिया अकाउंट पर भी साझा किया है जिसे करोड़ों लोग देख रहे हैं। पॉडकास्ट हिंदी तथा अंग्रेजी सहित कई प्रमुख भाषाओं में सुना जा सकता है।

पॉडकास्ट में संघ से उनके संबंधों को लेकर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में प्रधानमंत्री जी ने अपने बचपन को स्मरण करते हुए संघ के विषय में बात की। वो कैसे शाखा में गए, उन्होंने क्या देखा, किस बात ने उनको प्रभावित किया इत्यादि। इसके बाद उन्होंने कहा कि संघ एक बहुत बड़ा संगठन है। अब संघ 100 वर्ष का है। दुनिया में इतना बड़ा कोई और संगठन होगा मैंने नहीं सुना है। करोड़ों लोग उसके साथ जुड़े हैं। संघ को समझना इतना सरल नहीं हैं। संघ के काम को समझने का प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संघ व्यक्ति को "पर्पस आफ लाइफ" देता है, जीवन में एक दिशा देता है। देश ही सबकुछ है और जनसेवा ही प्रभु सेवा है, जो हमारे ग्रंथों में कहा गया है, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा, वही संघ कहता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉडकास्ट के उस मंच से संघ के आलोचकों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि संघ के स्वयंसेवक जीवन के हर क्षेत्र में सेवा करते है और कर रहे हैं। कुछ स्वयंसेवकों ने सेवाभारती नामक संगठन खड़ा किया है। यह सेवा भारती नामक संगठन के लोग गरीब बस्तियों में जाकर सेवा करते हैं। सेवा भारती के लगभग सवा लाख सेवा प्रकल्प चल रहे हैं वह भी बिना किसी सरकारी सहायता के। उन्होंने बताया कि संघ वनवासी कल्याण आश्रम चलाता है जिसमें स्वयंसेवक जंगलों में रहकर आदिवासियों की सेवा करते हैं। 70 हजार से भी अधिक एकल विद्यालय चल रहे हैं। अमेरिका में भी कुछ लोग हैं जो 10 से 15 डॉलर तक का दान देते हैं। एक कोकाकोला नहीं पियो और उतना पैसा एकल विद्यालय को दो। कुछ स्वयंसेवकों ने शिक्षा में क्रांति लाने के लिए विद्या भारती संगठन बनाया। जिसमें लाखों की संख्या में बालक –बालिकाएं अध्ययनरत हैं वह भी बहुत ही कम कीमत पर पढ़ाई हो रही है। विद्या भारती के विद्यालयों में विद्यार्थी जीवन के हर क्षेत्र से जुड़े हुनर भी सीख रहे हैं। संघ का एक सबसे बड़ा संगठन भारतीय मजदूर संघ भी एक बड़ा संगठन है जिसकी 55 हजार से अधिक यूनियन व करोड़ों सदस्य हैं। मजदूर संघ की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने वामपंथ और संघ के विचारों का अंतर भी स्पष्ट किया, उन्होंने कहा जहाँ अन्य संगठन कहते हैं, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ वहीं भारतीय मजदूर संघ कहता है मजदूर दुनिया को एक करते हैं, ये सोच का अंतर है। संघ 100 वर्षों से सभी प्रकार के चकाचौंध से दूर रहकर एकसाधक की तरह समर्पित भाव से कार्य कर रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मात्र कुछ उदाहरणों से ही संघ विरोधियों को बेनकाब कर दिया और अब यह पूरे विश्व में चर्चा में है। तुषार गांधी जैसे लोगों को भी शायद यह समझ में आ गया होगा कि संघ क्या है। संघ सदैव समाज सेवा में तत्पर संगठन है फिर वह चाहे किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा का समय हो जिसमें बाढ़, सूखा, भूकम्प, तूफान से लेकर अग्निकांड, रेल दुर्घटनाओं तक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बिना किसी प्रचार के सेवा में संलग्न हो जाते हैं। कोविड काल में जब पूरे भारत में लॉकडाउन था उस समय संघ भी के स्वयंसेवक आमजन को दवा और भोजन आदि उपलब्ध करा रहे थे जबकि तुषार गांधी जैसे आलोचक केवल सरकार की निंदा और अफवाहें फैलाने का ही कार्य कर रहे थे।

यह संघ की सेवाओं ही प्रयास व परिणाम रहा है कि करोड़ों की संख्या में आदिवासी व गरीब हिन्दू मतांतरित होने से बच सका है तथा लाखों की संख्या में मतांतरित हिंदुओं की घर वापसी हो रही है। जो लोग हिंदू सनातन धर्म का उन्मूलन करना चाहते हैं उनके सपने को कोई ध्वस्त कर रहा है तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का सपना जो पूरा हुआ है उसके पीछे भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व उसके समवैचारिक तथा आनुषांगिक संगठनों की तपस्या ही है। राष्ट्रीय स्वयंसवेक संघ की सामाजिक समरसता के कारण ही आज "एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे" तथा "बटेंगे तो कटेंगे" जैसे नारे लोकप्रिय हो रहे हैं।वर्तमान समय में महाकुंभ जैसे अत्यंत विशाल समागम जो सफल हो रहे हैं उनके पीछे भी संघ के छिपे हुए लाखों स्वयंसेवकों की सेवा ही रही है।

आज भारत का हिंदू अपने आप को गर्व से हिंदू कह रहा है तो यह संघ की अनथक तपस्या का ही परिणाम है और यही संघ विरोधियों की चिंता का सबसे बड़ा कारण भी है।

काँग्रेस गठबंधन शासित राज्यों में तुष्टीकरण की स्पर्धा

कर्नाटक सरकार सरकारी निर्माण कार्य में मुस्लिम ठेकेदारों को 4 प्रतिशत आरक्षण देगी

काँग्रेस और उनके गठबंधन वाली विभिन्न सरकारों में हिन्दू हितों को सीमित करके मुस्लिम तुष्टीकरण की मानों कोई स्पर्धा चल रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण की दिशा में एक सरकार कोई घोषणा करती है तो दूसरी सरकार उसका अनुसरण करते हुये और नई सौगात दौड़कर नया इतिहास बना रही है। इसे हिमाचल प्रदेश, तैलंगाना, झारखंड, कर्नाटक, केरल आदि सरकारों की घोषणाओं से समझा जा सकता हैं।

मुस्लिम तुष्टीकरण की यह स्पर्धा देश के नौ प्रदेशों में चल रही है। इनमें काँग्रेस अथवा उनके गठबंधन दलों की सरकारें हैं। इनमें कर्नाटक, हिमांचल, तैलंगाना, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाड और झारखंड जैसी सरकारें हैं। ये सरकारें दोनों प्रकार से तुष्टीकरण कर रही हैं। एक ओर मुस्लिम हितों का संवर्धन और दूसरी ओर हिन्दू हितों का शोषण। इसके लिये हिमाचल प्रदेश सरकार का नया निर्णय सामने आया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण का बजट तो बढ़ाया लेकिन सरकार की दो योजनाओं का व्यय

मंदिर ट्रस्ट के कंधे पर डाल दिया है। हिमाचल प्रदेश ही नहीं देशभर के अधिकांश मंदिरों ट्रस्ट के संचालन पर राज्य सरकारों का नियंत्रण होता है। यह हिमाचल प्रदेश में भी है। हिमाचल सरकार ने इसी का लाभ उठाया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुक्खू ने प्रदेश के सभी बड़े मंदिरों को पत्र लिखकर दो योजनाओं में आर्थिक सहायता मांगी है। इस पत्र के साथ ही मंदिर ट्रस्ट से जुड़े अधिकारियों ने सूची बनाकर इन मंदिरों से प्राप्त होने वाली कुल राशि का आकलन कर लिया है।इससे कयी कदम आगे अब कर्नाटक सरकार ने अपने बजट में मुस्लिम समाज को सशक्त बनाने केलिये घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के पास वित्त विभाग भी है। उन्होने पिछले दिनों वर्ष 2025–26 केलिये अपनी सरकार का बजट प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने बजट में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिते एक दो नहीं कुल तेरह योजनाओं की घोषणा की हैं। इसमें सबसे बड़ी घोषणा है सरकारी ठेकों में मुस्लिम ठेकेदारों को चार प्रतिशत आरक्षण देना। इस निर्णय के साथ ही अब कर्नाटक में शासकीय, अर्ध शासकीय निर्माण कार्य के ठेकों में चार प्रतिशत कार्य मुस्लिम ठेकेदारों को ही दिये जायेंगे। अब तक विभिन्न राज्य सरकारों ने सरकारी नौकरियों में तो मुसलमानों को आरक्षण का प्रावधान किया है। लेकिन ठेकों में आरक्षण देने की घोषणा करने वाला कर्नाटक पहला राज्य बन गया है। सरकारी ठेकों में मुस्लिम आरक्षण की घोषणा के साथ कर्नाटक में इमामों को छै हजार रुपये मासिक भत्ता देने, मुस्लिम लड़कियों के लिए 15 नये महिला महाविद्यालय खोलने की घोषणा भी की है । ये नये महाविद्यालयों का निर्माण बक्फ की जमीन पर होगा। लेकिन इनके निर्माण कार्य पर पूरा पैसा सरकार लगायेगी। इनके संचालन में बक्फ बोर्ड की भूमिका प्रमुख होगी। तुष्टीकरण की अन्य घोषणाओं में अल्पसंख्यक समाज के सामूहिक विवाह आयोजित करने वाले अशासकीय संगठनों को प्रति जोड़े पचास हजार रुपये की राशि देने, 250 मौलाना आजाद मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल में चरणबद्ध तरीके से 'प्री–प्राइमरी' से पूर्व विश्वविद्यालय कक्षाएं शुरू करने, उर्दू माध्यम की शिक्षा देने वाले सौ विद्यालयों को अनुदान के रूप में सौ करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना पर कुल चार सौ करोड़ का व्यय अनुमानित है। इसमें सौ करोड़ की राशि इस वर्ष केलिये है। कर्नाटक के विभिन्न नगरों में अल्पसंख्यक समाज केलिये अलग कॉलोनियों का विकास होगा। इस मद पर एक हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। वक्फ संपत्तियों और कब्रिस्तानों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार 150 करोड़ रुपये व्यय करेगी। मुस्लिम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 50 लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में नए आईटीआई कॉलेज की स्थापना की जायेगी ताकि मुस्लिम

समाज के बच्चों का "स्किल डेवलपमेंट हो सके। इनमें मुस्लिम छात्रों के लिए 50 प्रतिशत शुल्क की छूट दी जायेगी। इसके अतिरिक्त उलाल नगर में मुस्लिम लड़कियों के लिए आवासीय महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी। जो मुस्लिम छात्र विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए छात्रवृत्ति में वृद्धि की जायेगी। बेंगलुरु नगर के हज भवन का विस्तार किया जायेगा। इसके साथ मुस्लिम छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने की भी घोषणा की गई है। कर्नाटक सरकार का कुल बजट 4.09 करोड़ का है। इसमें मुस्लिम और ईसाई समाज को लगभग 4700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। एक सामान्य नागरिक की भाँति कर्नाटक के अल्पसंख्यक समाज को अन्य प्रावधानों के लाभ तो मिलेंगे ही। इनके साथ अल्पसंख्यक कल्याण के इन प्रावधानों का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

कर्नाटक में काँग्रेस सरकार द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण की ये घोषणाएँ पहली नहीं हैं। कर्नाटक सरकार धर्म के आधार पर मुस्लिम समाज को चार प्रतिशत आरक्षण की घोषणा पहले की जा चुकी है। मुस्लिम समाज को यह चार प्रतिशत आरक्षण हिन्दुओं के ओबीसी समुदाय के आरक्षण कोटे से दिया जाना है। ओबीसी हिन्दू समाज का एक वर्ग समूह है। इस वर्ग के लिये आरक्षण कोटे की सीमा 32 प्रतिशत है। इस वर्ग में मुस्लिम समाज को शामिल करने का अर्थ है हिन्दू समाज के ओबीसी समूह के हितों में चार प्रतिशत की कटौती हो जायेगी। कर्नाटक में ओबीसी कोटे से मुसलमानों को यह आरक्षण काँग्रेस ने पहले भी लागू किया था। लेकिन बीच में भाजपा सत्ता में आई तो ओबीसी कोटे से मुसलमानों को आरक्षण दिये जाने इस निर्णय को बदल दिया था। लेकिन कर्नाटक में दोबारा काँग्रेस की सरकार आई तो यह निर्णय पुनः लागू हो गया। कर्नाटक सरकार द्वारा की गईं इन नई घोषणाओं उलेमाओं के उस तेरह सूत्रीय मांगपत्र की झलक है जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जारी हुआ था। उसमें उर्दू भाषा के विकास, सरकारी ठेकों में प्राथमिकता, मुस्लिम कॉलोनी के विकास आदि की मांगे शामिल थीं। एक मांग में थोड़ा अंतर आया है। तब उलेमाओं ने सेना और पुलिस भर्ती में मुसलमान युवकों को प्राथमिकता देने की माँग की गई थी। कर्नाटक सरकार की घोषणा में यह विन्दु तो नहीं है। लेकिन मुस्लिम लड़कियों को "आत्मरक्षा प्रशिक्षण" की घोषणा की गई है। इससे उनकी क्षमता में वृद्धि होगी जो पुलिस एवं सेना की भर्ती स्पर्धा में लाभ देगा। कर्नाटक राज्य के बजट की एक विशेषता और है। इस बजट में एक ओर अल्पसंख्यक कल्याण के लिये उदारता से नई नई घोषणाएँ कीं गई हैं वहीं दूसरी ओर सरकार के खजाने में मंदिरों से होने वाली आय में वृद्धि का आकलन किया गया है । कर्नाटक के मंदिरों से होने वाली इस आय वृद्धि पर यद्यपि सरकार ने कुछ नहीं कहा लेकिन कर्नाटक के अर्थशास्त्रियों के आकलन के अनुसार इस वर्ष कर्नाटक सरकार को मंदिरों से होने वाली आय में चार प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। मंदिरों में होने वाली आय का मुख्य स्त्रोत श्रद्धालुओं का दान और चढ़ावा होता है। जाग्रति के साथ मंदिरों में जाने वाले श्रृद्धालुओ की संख्या भी बढ़ रही है और दान का औसत भी। इसी के कारण यह वृद्धि अनुमानित है। अन्य राज्यों की भाँति कर्नाटक में भी सरकार अनेक मंदिर ट्रस्ट संचालन में सहभागिता है। यह आय इन्हीं मंदिरों से होती है। इससे स्पष्ट है कि सरकार मंदिरों से तो धन लेगी और मुस्लिम तुष्टीकरण पर व्यय करेगी।

कर्नाटक में ओबीसी कोटे से मुसलमानों को यह आरक्षण काँग्रेस ने पहले भी लागू किया था। लेकिन बीच में भाजपा सत्ता में आई तो ओबीसी कोटे से मुसलमानों को आरक्षण दिये जाने इस निर्णय को बदल दिया था।

बलूचिस्तान - सतत संघर्ष

प्रशांत पोळ

बलूचिस्तान को प्रकृति ने बहुत कुछ दिया हैं. विस्तीर्ण भू प्रदेश हैं, जिसमे रेगिस्तान हैं, जंगल हैं, दर्रे हैं, समंदर हैं, बर्फ हैं...! सब कुछ हैं, इस प्रदेश में पाकिस्तान का आधे से थोड़ा कम हिस्सा याने बलूचिस्तान लेकिन जनसंख्या के मामले में मात्र बहुत कम। पाकिस्तान का हर पांचवा आदमी बलूचिस्तान से होता हैं।

राजधानी क्वेट्टा, बेहद खूबसूरत शहर हैं। यह फलों का शहर हैं। शहर के चारों ओर फलों के बगीचे। भरपूर फल, सूखे मेवों से सजे बाजार और शाम की ठंडी हवाएं। किसी समय क्वेट्टा 'छोटा पेरिस' कहलाता था। लेकिन आज नाही। आज क्वेट्टा, बमों के धमाकों से पहचाना जाता हैं।

पाकिस्तान को जो 990 किलोमीटर का सागर किनारा मिला हुआ हैं, वह दो राज्यों के पास हैं – सिंध (270 किलोमीटर) और बलूचिस्तान (मकरान 720 किलोमीटर)। सिंध के पास कराची जैसा विशाल बंदरगाह हैं, तो बलूचिस्तान के पास, अभी–अभी चीन का बनाया हुआ अत्याधुनिक ग्वादर बंदरगाह हैं।

कराची से ईरान की तरफ यदि हम अरेबियन समुद्र के किनारे से, ओमान की खाड़ी में बढ़ते जाते हैं, तो बलूचिस्तान राज्य के सोनमियानी, ओरमारा, कालमत, पासनी ऐसे बंदरगाह आते हैं। लेकिन ईरान की सीमा के पास, ओमान के सामने बना ग्वादर बंदरगाह भव्यतम हैं। यह बंदरगाह याने बलूचिस्तान की आजादी के रास्ते में खड़ी एक दीवार हैं...! चूंकि ग्वादर बंदरगाह का विकास चीन ने किया हैं, इसलिए इस बंदरगाह की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी चीन ने ली हैं। अगले चालीस वर्षों का ग्वादर का स्वामित्व (लीज) चीन के पास हैं। इसलिए चीन वहाँ अपनी नौसेना का अड्डा बना रहा हैं। इसी संदर्भ में दो महीने पहले, पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख, अमजद खान नियाजी और चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू के बीच रक्षा सहयोग पर सहमति बनी हैं। इसका अर्थ स्पष्ट हैं–ग्वादर और उसके आस पास के समुद्री इलाके में चीनी फौजों की संख्या बढ़ने जा रही हैं। बलोचिस्तान के लोगों को यह सब पसंद नहीं हैं। गुलामी की जंजीरे जकड़ती जा रही हैं, ऐसा उन्हे लगता हैं।

ग्वादर बंदरगाह यह चीन की महत्वाकांक्षी सी पी ई सी (China Pakistan Economic Corridor) परियोजना का हिस्सा हैं। ग्वादर को चीन के शिंजियांग प्रांत से जोड़ने के लिए चीन, 2442 किलोमीटर का आधुनिक रास्ता, पाकिस्तान में बना रहा हैं। चीन को लगने वाला तेल (पेट्रोलियम पदार्थ) और मछली, चीन ग्वादर से, सड़क मार्ग से, अपने देश तक लेकर जाना चाहता हैं। किन्तु बलोच लोगों के विरोध से, और पाकिस्तानी व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार से यह रास्ता पूरा नहीं बन पाया हैं। बलोचिस्तान के नागरिक इस परियोजना का और चीनी नागरिकों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं।

बलूचिस्तान किसी जमाने में विशाल भारत का हिस्सा था।

इससे पहले हमने देखा हैं की समूचा बलूचिस्तान, उन दिनों गांधार महाजनपद का हिस्सा था। किन्तु बलूचिस्तान के आज भी भारत से काफी निकट के संबंध हैं, रिश्ते हैं। एक संबंध, हजारो वर्ष पुराने रिश्तों की कड़ीयाँ जोड़ता हैं। बलूचिस्तान के कलात में जो ब्राहुई भाषा बोली जाती हैं, वह अपने दक्षिण भारत की द्रविडियन भाषा का ही एक प्रकार हैं। तमिल, कन्नड और तेलगु से बहुत कुछ मिलती – जुलती हैं। इस भाषा के अनेक शब्द तामिल, कन्नड भाषाओं से लिए गए हैं। त्रिचनापल्ली के एक मित्र ने बताया की उसने जब यह ब्राहुई भाषा की यू–ट्यूब चैनल देखी, तो उसे बहुत कुछ

समझ में आया कुछ समान शब्द –
तुम (You) – नी
आंखे (Eye) – कन
थूकना (Spit) – थुप्पू
पुत्र – लड़का (Son) – मखम यार

रोबर्ट कॉलवेल्ड (1814–1891) ने इन दोनों भाषाओं की समानता पर बहुत अध्ययन किया हैं। उन्होने यह प्रमाणित किया हैं की ब्राहुई भाषा में तामिल एवं कन्नड के अनेक शब्द हैं। साथ ही दोनों भाषाओं की शैली भी एक जैसी हैं। किन्तु कालांतर से ब्राहुई भाषा, फारसी लिपि में लिखी जाने लगी हैं। बलूचिस्तान से भारत का दूसरा रिश्ता पिछले ढाई सौ–पौने तीन सौ वर्ष पुराना हैं। पानीपत के तीसरे युध्द में अहमद शाह अब्दाली के हाथों पराजित होने के बाद, मराठा सेना के लगभग बीस – पच्चीस हजार सैनिकों और महिलाओं को अब्दाली अपने साथ ले गया। रास्ते में पंजाब में सीख सेनानियों ने कुछ महिलाओं को तो छुड़वा लिया, किन्तु बाकी मराठों को बंदी बनाकर ले कर जाने में वह सफल रहा। अब्दाली का रास्ता बलूचिस्तान होकर जाता था। पानीपत के युध्द में, लूट और खजाना मिलने की आशा में, उसे बलूच सरदारों ने काफी सहयोग दिया था। इस पानीपत के युद्ध में मराठे हारे तो अवश्य, किन्तु उन्होंने इतना जबरदस्त संघर्ष किया, की अब्दाली के हाथ कुछ ज्यादा न लग सका। इसलिए अब्दाली ने खजाने के बदले, सभी बीस–पच्चीस हजार मराठे, गुलाम के रूप में, बलूच सरदारों को दे दिये। वस्तुतः पानीपत के युध्द में अब्दाली की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो जीत जरूर गया था, लेकिन उसकी कमर टूट गई थी। (इसीलिए, अब्दाली के बाद, किसी ने भी खैबर के दर्रे से भारत पर आक्रमण की हिम्मत नहीं की)। अब्दाली को इन बीस–पच्चीस हजार मराठा कैदियों को ढो कर अफगानिस्तान ले जाना संभव ही नहीं था।

वे बीस–पच्चीस हजार मराठा सैनिक वही बस गए। पहले बुगती और मर्री समुदाय के नौकर के रूप में रहने वाले मराठा सैनिक, बाद में अपने बलबूते पर उन्ही समुदायों के हिस्सा बन गए।

आज लगभग 25 लाख मराठा, बुगती और मर्री समुदाय में हैं. ये सब मुस्लिम हो गए हैं, लेकिन अपने मूलाधार भूले नहीं। ये सब अपने नाम के आगे 'मराठा' लिखते हैं। उनके बहुत से रीति रिवाज, विवाह पद्धती, महाराष्ट्र की परंपरा से मिलते जुलते हैं. उनका एक संगठन हैं – 'मरहट्टा कौमी इत्तेहाद ऑफ बलोचिस्तान' (Marhtta Qaumii Ittehad of Balochistan)। इस समुदाय के प्रमुख व्यक्ति हैं – वडेरा दीन मुहम्मद मराठा (जमींदार दीन मुहम्मद मराठा)। डेरा बुगती और सुई हिन्दू समुदाय, इन वडेरा दीन मुहम्मद साहब को इज्जत और सम्मान देता हैं।

इन सब की स्वाभाविक कड़ी, पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ती हैं। बहुत पहले से बलूचिस्तान अलग था और इसीलिए आज भी इनको पाकिस्तान के साथ रहना नहीं हैं और भी कारण हैं।

बलूचिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का भंडार हैं। विशेषतः प्राकृतिक गॅस बड़े पैमाने पर निकलती हैं, जो पाकिस्तान सरकार के आमदनी का बड़ा हिस्सा हैं। लेकिन जहां से यह गॅस निकलता हैं, उस बलूचिस्तान के पास उस आमदनी का अत्यंत नगण्य ऐसा, छोटा सा हिस्सा आता हैं। इस कारण बलूचिस्तान प्रांत में विकास का चित्र कही दिखता नहीं हैं। अभी कुछ वर्षो में ग्वादर बंदरगाह पर जानेवाला जो एक्सप्रेस–वे चीन ने बनाया हैं, उसे छोड़ा दिया जाय, तो बलूचिस्तान में आज भी आधारभूत संरचना (इनफ्रास्ट्रक्चर) की भारी कमी हैं और इसीलिए बलूच लोगों ने, 27 मार्च 1948 को, जब पाकिस्तान ने उसे बलात अपने कब्जे में लिया, तब से पाकिस्तान के विरोध में विद्रोह का स्वर बुलंद किया हैं।

क्रान्तिकारी पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी

रमेश शर्मा

25 मार्च 1931 क्रांतिकारी पत्रकार गणेशशंकर विद्यार्थी का बलिदान चंद्रशेखर आजाद और भगतसिंह की भेंट इन्हीं ने कराई थी राष्ट्र और संस्कृति को सर्वोपरि मानते थे।

सार्वजनिक जीवन या पत्रकारिता में ऐसे नाम विरले हैं जिनका व्यक्तित्व व्यापक है और जो विभिन्न विचारों में समन्वय बिठा कर राष्ट्र और संस्कृति की सेवा में समर्पित रहे हों। ऐसे ही क्राँतिकारी पत्रकार थे गणेश शंकर विद्यार्थी। उन्हे उनके जीवन में और जीवन के बाद भी सब अपना मानते हैं। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अहिसंक आँदोलन में जहाँ स्वयं सीधे जुड़े थे तो वहीं क्राँतिकारी आँदोलन के बलिदानियों के अज्ञातवास की व्यवस्था करते थे। यह व्यवस्था उनके रुकने से लेकर धन प्रबंध तक होती थी। वे पाँच बार जेल गये। वे राष्ट्र के लिये सामाजिक और साम्प्रदायिक एकता आवश्यक मानते थे और कहते थे कि राष्ट्र का आधार समन्वय और सद्भाव है संस्कृति राष्ट्र पहचान है। पूजा उपासना पद्धति पृथक होने से राष्ट्रीयता नहीं बदलती। इसलिये सबके लिये राष्ट्र और संस्कृति सर्वोपरि होना चाहिए। वे सदैव इसी अभियान में लगे रहे और इसी अभियान में उनका बलिदान भी हुआ।

गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म 26 अक्टूबर 1890 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अतरसुइया मोहल्ले में हुआ था। प्रयागराज का नाम उन दिनो इलाहाबाद हुआ करता था। उनके पिता जयनारायण श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश में ही फतेहपुर के निवासी थे लेकिन मध्यप्रदेश के मुंगावली में आकर बस गये थे। यहां प्रधान अध्यापक थे और इसी स्थान को उन्होंने अपना स्थाई निवास बना लिया था। मुंगावली अशोकनगर जिले के अंतर्गत यह एक तहसील मुख्यालय है। प्रयागराज विद्यार्थी का ननिहाल था। गर्भ अवस्था में माता गोमती देवी मुंगावली से अपने मॉयके प्रयागराज गयीं और विद्यार्थी जी का जन्म वहीं हुआ। नानी गंगा देवी गणेश जी की भक्त थीं। नाम "गणेश शंकर" उनकी नाना गंगा देवी ने ही रखा था। शिक्षा और साहित्य विधा में ननिहाल भी परिवार प्रतिष्ठित था इस नाते विद्यार्थी के ननिहाल की निकटता प्रयागराज में नेहरु परिवार से भी थी और प्रेमनारायण श्रीवास्तव परिवार से रिश्तेदारी भी। प्रेम नारायण जी यनि अभिताभ बच्चन के दादाश्री। विद्यार्थी जी की मित्रता बचपन में पं. जवाहरलाल नेहरु से हुई जो आखिर तक रही। लेकिन यह मित्रता विद्यार्थी जी की पत्रकारिता और प्रखर राष्ट्र भाव जाग्रति के अभियान में बाधा न बनी। उनके संबंध कितने गहरे रहे होंगे इसका अनुमान इस एक बात से लगाया जा सकता है कि विद्यार्थी जी के विरुद्ध लगाये गये एक मानहानि मुकदमे में गवाही देने के लिये पं. जवाहरलाल नेहरू अदालत तक गये थे। यह बात अलग है कि न्यायधीश ने गवाही के तथ्य को शंकित माना और विद्यार्थी जी को सजा सुना दी। ठीक इसी प्रकार वे गाँधी जी के प्रशंसक थे। वे गाँधी जी के व्यक्तित्व को चमत्कारिक कहते थे किंतु स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से तालमेल के पक्ष में नहीं थे। असहयोग आँदोलन में जब गाँधी जी ने खिलाफत आँदोलन को सम्मिलित किया तो इस पर भी विद्यार्थी जी ने असहमति को प्रदर्शित करते प्रताप में संपादकीय लिखा था। उनका मानना था कि खलीफा व्यवस्था का समर्थन करना है तो यह आँदोलन अलग हो और भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन अलग। 1913 के बाद के उनके तमाम लेखों में पूर्ण स्वतंत्रता का अव्हान ही होता था। जो नारा तिलक जी ने दिया था।

विद्यार्थी जी की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के सानिध्य में मुंगावली में ही हुई, और मिडिल परीक्षा 1905 में विदिशा नगर से। महाविद्यालयीन शिक्षा वे पुनः प्रयागराज आये। यहीं से उनका सार्वजनिक जीवन आरंभ हुआ। लेखन में रुचि बचपन से थी। यह विधा उन्हे विरासत में मिली थी। पिता और नाना दोनों परिवार शिक्षा और साहित्य सृजन से जुड़े थे। इस नाते लेखन चिंतन उनके रक्त में आया। जब वे सोलह वर्ष के थे तब उनकी रचना "सरस्वती" पत्रिका में हुई थी। महाविद्यालयीन शिक्षा के दौरान वे सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी लेखक पत्रकार पं सुन्दर लाल और साहित्यकार एवं पत्रकार पं महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आये। साहित्य में द्विवेदीजी को और पत्रकारिता में पं सुन्दर लाल को वे अपना आदर्श और गुरु मानते थे। साहित्य एवं पत्रकारिता में यह अंतर्धारा उनके प्रत्येक लेखन में झलकती है। उन्हे पढ़ने और लिखने का शौक बचपन से था इसी शौक ने उन्हें लेखक पत्रकार बनाया। उन्होंने सोलह वर्ष की आयु में "आत्मोसर्जना" लघु उपन्यास लिख दिया था। प्रयागराज में अपनी पढ़ाई के साथ उनकी रचनायें पत्र पत्रिकाओं में स्थान बनाने लगीं थीं। परिचय भी

बढ़ा और समय के साथ "कर्मयोगी" के संपादकीय विभाग में सहयोगी हो गये थे। वे लेखन में अपने नाम आगे परिवार का पारंपरिक उपनाम "श्रीवास्तव" की बजाय "विद्यार्थी" लिखते थे। वे कहते कि अभी मैं विद्यार्थी हूँ इसलिये लिखता हूं। 1908 में अपनी पढ़ाई पूरी करके वे कानपुर आ गये यहाँ पहले करेंसी आफिस में नौकरी कर ली। तब उन्हें तीस रुपये माहवार वेतन मिला करता था। लेकिन अध्ययन और लिखना सतत जारी रहा उनके लेखन में समाज को जाग्रत रहने और स्वयं के सम्मान का ध्यान रखने का आव्हान होता था। लेखन की यह विधा अंग्रेज अधिकारी को पसंद न थी। इसलिये विवाद हुआ और वे नौकरी छोड़कर हाई स्कूल में शिक्षक हो गये। विद्यालय का वातावरण उनके अनुकूल था। पठन–पाठन और लेखन का कार्य तेज चला। कर्मयोगी, स्वराज्य और कलकते की हितवार्ता में वे नियमित लिखते। 1911 में वे शिक्षक की नौकरी छोड़कर पत्रिका सरस्वती में सहायक हो गये। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक थे। यहाँ वे दो वर्ष रहे। 9 नवम्बर 1913 को उन्होंने प्रताप नाम से अपनी पत्रिका आरंभ की। यह नाम उन्होंने महाराणा प्रताप के ओज के रूप में माना था। प्रताप निकालने का निर्णय लिया तब उनकी आयु तेइस वर्ष की थी। परिवार की विरासत, अध्ययन और आयु का ओज इनकी त्रिवेणी ने उनका विचार बनाया था कि राष्ट्र का निर्माण महाराणा प्रताप जैसी संघर्ष शीलता और समर्पण से ही संभव है इसलिये उन्होंने पत्रिका का नाम "प्रताप" रखा। सात वर्ष पश्चात 1920 में प्रताप को दैनिक कर दिया।

भारत की स्वतंत्रता और सार्वजनिक अभियान में ऐसा कोई नहीं था जो उनके नाम और निर्भीक लेखन से परिचित न हो ।

भारत की स्वतंत्रता और सार्वजनिक अभियान में ऐसा कोई नहीं था जो उनके नाम और निर्भीक लेखन से परिचित न हो। 1916 में तिलक जी उनके कार्यालय आये थे। पत्रकारिता, लेखन, और समाज सेवा के साथ वे एनीवेसेन्ट के होमरूल आँदोलन से जुड़े थे। नेहरु जी के आग्रह पर विद्यार्थी जी काँग्रेस के सदस्य बन गये। वे 1925 में काँग्रेस के कानपुर अधिवेशन में स्वागताध्यक्ष बने और बाद मै उत्तरप्रदेश काँग्रेस के अध्यक्ष भी बने। उन्होनें 1930 के सत्याग्रह में हिस्सा भी लिये और जेल गये। विद्यार्थी जी काँग्रेस के सदस्य तो बन गये पर न तो उनके लेखन की दिशा बदली और न अन्य गतिविधियँ। उन्होंने प्रताप के कार्यालय के नीचे एक गुप्त तहखाना बनाया हुआ था जहाँ देश का समस्त प्रतिबंधित साहित्य एकत्र रहता था और वही क्राँतिकारियों के छिपने का स्थान था। विद्यार्थी जी को प्रताप में माखनलाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण शर्मा नवीन जैसे सहयोगी मिल गये। इनके कारण प्रताप की यात्रा निर्वाध रही। विद्यार्थी जी के आँदोलन में जाने अथवा जेल जाने का प्रताप पर कोई अंतर न पड़ता था। सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी भगतसिंह ने अपने अज्ञातवास का ढाई वर्ष का काल–खंड विद्यार्थी जी के सानिंध्य में ही गुजारा। वे "बलवंतसिंह" के नाम से प्रताप में काम करने लगे और इसी नाम से लेख लिखते। यह समाचार पत्र "प्रताप" की क्रॉंतिकारी आवाज थी कि तब कलकत्ता और पंजाब के बाद कानपुर ही क्रांतिकारी गतिविधियों का केन्द्र बन गया। प्रताप में भगतसिंह ही नहीं राम दुलारे त्रिपाठी ने भी काम किया। इन्हें भी काकोरी कांड में सजा हुई थी। गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने ही अपने कार्यालय में क्राँतिकारी चंद्र शेखर आजाद और भगतसिंह की भेंट कराई थी। विद्यार्थी जी की प्रेरणा से ही श्यामलाल जी गुप्त ने "विश्व विजयी तिरंगा प्यारा" झंडा गीत लिखा और यहीं माखन लाल चतुर्वेदी जी ने अपना कालजयी गीत पुष्प की अभिलाषा लिखा। ये दोनों गीत सबसे पहले प्रताप में प्रकाशित हुये। विद्यार्थी जी के प्रयत्न से ही झंडा गीत कानपुर में काँग्रेस अधिवेशन में गाया गया। विद्यार्थी जी के प्रयत्न से ही क्राँतिकारी अशफाक उल्ला खान की कब्र बन सकी। बलिदानी अशफाक उल्ला को 1927 में फैजाबाद जेल में फाँसी दी गयी थी।

विद्यार्थी संस्कृत, हिन्दी, उर्दू फारसी और अंग्रेजी भाषाओं के जानकार थे। उनकी भाषा सरल शुद्ध और मुहावरेदार होती थी। पत्रकारिता में शुद्ध, सरल और मुहाबरे दार भाषा का चलन विद्यार्थी जी ने ही आरंभ किया था। उनका प्रत्येक पल राष्ट्र, संस्कृति और पत्रकारिता के लिये समर्पित था। पर यह जीवन यात्रा दीर्घ जीवी न रह सकी। मात्र 41 वर्ष की आयु में ही उनका बलिदान हो गया। वह 25 मार्च 1931 का दिन था। कानपुर बंद का आयोजन हुआ था। यह बंद क्राँतिकारी भगतसिंह को फाँसी दिये जाने के विरोध में आयोजित था। क्राँतिकारी भगतसिंह को 23 मार्च को फाँसी दी गई थी। गम, गुस्से और विरोध में देश के विभिन्न स्थानों पर बंद का आयोजन हुआ। इसकी पहल विद्यार्थी जी और प्रताप ने की थी। लेकिन मुस्लिम लीग और कुछ संगठन थे जिन्होंने बंद का विरोध किया 24 मार्च से कानपुर में साम्प्रदायिक दंगे शुरु हो गये। विद्यार्थी जी को लगा कि वे दंगाइयो को जाकर समझा सकते हैं कि भगतसिंह का बलिदान इस राष्ट्र की स्वाधीनता के लिये हुआ है। सबको मिलकर विरोध करना चाहिए। हालांकि प्रताप के सहयोगियों ने विद्यार्थी जी को रोकना चाहा पर वे न रुके। विद्यार्थी जी जितने सरल और सहज थे उतने ही अपने निर्णय और लेखन पय दृढ़ रहते थे। वे न माने और समझाने के लिये दंगाइयो के बीच चले गये। वस न लौट सके। दो तीन बाद दंगा थमा तब विद्यार्थी जी को ढूंढने का प्रयत्न हुआ। लेकिन वे कहीं न मिले अंत में 29 मार्च को उनका शव 'अज्ञात शवों' के ढेर में मिल सका। देखकर लगा कि शव के साथ भी अमानुषिकता बरती गयी। शव निकाला और अंतिम संस्कार किया गया। किस गली में प्रहार हुआ किसने किया यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है।

सेवा, सुरक्षा और सुशासन की सरकार : योगी

उत्तर प्रदेश सरकार के आठ वर्ष पूरा होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोकभवन में पत्रकार वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सेवा सुरक्षा और सुशासन की सरकार के आठ साल पूरे होने जा रहे हैं, इसमें प्रदेश की जनता का व्यापक समर्थन भी मिला है। इसके लिए उन्हें मैं बधाई देता हूं।

मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था, कृषि, निवेश, रोजगार, नौकरी, स्वास्थ्य समेत विभिन्न क्षेत्रों में आठ साल हुए कार्यों के बारे में विस्तार से बताया।

यू.पी. आज विकास का इंजन –

सीएम योगी ने बताया कि 25, 26 और 27 मार्च को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों को उत्सव के माध्यम से जनता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आठ वर्ष पहले की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। पहले पहचान का संकट था, किसान आत्महत्या करता था, युवा बेरोजगार था, बेटी असुरक्षित थी, दंगों से लोग परेशान थे। इन सभी बातों को प्रदेश ने देखा है और झेला है। सरकार बदलने से इन आठ वर्षों में जो बदलाव हुआ, उसे सब महसूस कर रहे हैं। यूपी आज विकास का इंजन बनकर उभरा है।

सबका साथ, सबका विकास –

उत्तर प्रदेश में समग्र विकास पर हमारा जोर है। हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा, एक समय में यूपी में किसान आत्महत्या करता था। यूपी अब कृषि प्रधान राज्य है। हम खाद्यान्न के क्षेत्र में नई ऊंचाई पर हैं। यूपी में अब 20% अधिक खाद्यान्न उत्पादन है।

पीएम किसान निधि के तहत यूपी में 2.61 लाख किसानों को धनराशी मिली है। कृषि से जुड़ी कई लंबित योजनाओं को हमने पूरा किया। इसके अलावा यूपी में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। अब यूपी में अराजकता नहीं है। यूपी की अर्थव्यवस्था अब नई ऊंचाई पर है। उन्होंने कहा 8 वर्षों में सिर्फ जनता के लिए काम किया। प्रदेश मे सुदृढ़ कानून व्यवस्था के कारण अपराध तथा अपराधियों पर लगाम लगा, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश हुआ।

बीते 8 वर्षों में प्रदेश सरकार ने 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की है। समाज में सशक्त नारी, समृद्ध समाज हुआ है।

सबका साथ, सबका विकास

यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार के आठ साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने आठ साल पूरे हो गए हैं। साल 2017 में बीजेपी को जनता प्रचंड बहुमत दिया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। सीएम योगी ने अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा किया। जिसमं करोना जैसी आपदा भी रही। फिर साल 2022 में दोबारा हुए विधानसभा चुनाव में भी यूपी की जनता ने दिल खोलकर बीजेपी को वोट दिया, जिसके बाद बीजेपी नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ को ही यूपी के सीएम के तौर पर चुना। संगठन सरकार के समन्वय से डबल इंजन की सरकार निरन्तर सुराज की ओर बढ़ रही है।

योगी सरकार के आठ साल पूरे होने पर प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी इसे जश्न के तौर पर मना रही है। इस संबंध में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच योगी सरकार के आठ सालों के दौरान जनता के लिए कौन से काम किए गए, कौन सी योजनाएं लाई गईं ये ज्यादा अहमियत रखती हैं। योगी सरकार की योजनाओं और उनके काम की बदौलत ही यूपी में उनकी दोबारा सरकार बन सकी। ऐसे में चलिए एक बार योगी सरकार के आठ साल के कार्यकाल पर एक नजर डालते हैं।

गरीब कल्याण — **लक्ष्य: जीरो पावर्टी**

- प्रदेश सरकार ने बीते आठ वर्षों में 5.94 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की है।
- गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को और गति देने के लिए गांधी जयंती, 2 अक्टूबर 2024 को 'जीरो पावर्टी कार्यक्रम' की शुरुआत की गई।
- इस मिशन के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में सबसे निर्धन परिवारों की पहचान कर उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
- सरकार की योजना है कि इन परिवारों को ऐसी आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जाए, जिससे उनकी वार्षिक आय न्यूनतम ₹1.25 लाख तक सुनिश्चित की जा सके।
- अब तक इस योजना के अंतर्गत 13.57 लाख परिवारों की पहचान की जा चुकी है और इन्हें सरकार की 17 विभिन्न योजनाओं के कन्वर्जेन्स (समन्वय) के साथ जोड़ा गया है, जिससे उन्हें व्यापक लाभ मिल सके।
- **प्रमुख योजनाएँ, जिनसे वंचितों को जोड़ा जा रहा है:** राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, विद्यालयों में प्रवेश, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अपरेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, जल जीवन मिशन, स्वच्छ शौचालय।
- प्रदेश में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों और कोविड काल में निराश्रित हुए बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रत्येक मंडल में सर्वसुविधायुक्त अटल आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं।
- सेवामित्र पोर्टल पर अब तक 52,064 कुशल कामगारों का पंजीकरण हो चुका है।
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 6,92,564 लाभार्थी पंजीकृत किए गए हैं।
- अटल पेंशन योजना के माध्यम से 93 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं।
- प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 9.52 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं।
- कार्यस्थल पर श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में 5 लाख रुपये, स्थायी दिव्यांगता पर 3 लाख रुपये तथा आंशिक दिव्यांगता पर 2 लाख रुपये की सहायता।
- पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये और सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपये का लाभ दिया जाता है।
- दिव्यांगता की स्थिति में योजनानुसार 2 लाख से 4 लाख रुपये तक की सहायता तथा अंत्येष्टि के लिए 25,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है।

अन्त्योदय से सर्वोदय

- आठ सालों में 2.62 करोड़ से अधिक इज्जत घर का निर्माण
- कोरोना काल के बाद से 14.70 करोड़ लोगों को निशुल्क राशन
- 1.86 करोड़ से अधिक उज्जवला कनेक्शन
- 2017 के अबतक 56 लाख से अधिक आवास

अपराधियों के खिलाफ एक्शन

- यूपी के सात जिलों में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था
- उ0प्र0 स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नाम के नए सुरक्षा बल का गठन

- यूपी–112 का रिस्पांस टाइम 7 मिनट 24 सेकेंड करना
- योगी सरकार में 222 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, 8118 घायल

महिलाओं की सुरक्षा

- यूपी में एंटी रोमिया स्क्वाड का गठन
- तीन महिला पीएसी बटालियन का गठन
- मिशन शक्ति जैसे अभियान
- रात में महिलाओं की कॉल पर पीआरवी की व्यवस्था

स्मार्ट सिटी और शहरों का विकास

- 125 नए नगर निकायों का गठन
- लखनऊ में एआई सिटी का क्रियान्वयन
- 17 शहरों का स्मार्ट सिटी के तौर पर विकास
- नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर और आगरा में मेट्रो सेवा

यूपी की ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी

- यूपी में 6 एक्सप्रेसवे संचालित, 11 पर चल रहा काम
- गौतमबुद्धनगर में जेवर एयरपोर्ट का निर्माण
- देश का सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य
- भारत की कुल मोबाइल निर्माण में 45% योगदान

किसानों का सम्मान

- कृषि विकास दर 8.6% से बढ़कर 13.7% हुई
- हर साल 4 करोड़ टन फल और सब्जियों के उत्पादन के साथ देश में पहला स्थान
- पीएम कुसुम योजना से किसानों को 76189 सोलर पंपों का आवंटन
- 27 नवीन मंडी स्थलों का आधुनिकीकरण

हर घर रोशन

- ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटे, तहसील क्षेत्रों में 22 घंटे और जिला मुख्यालय में 24 घंटे बिजली
- अयोध्या को सोलर सिटी और बुंदेलखंड एक्सप्रेस–वे को सोलर एक्सप्रेसवे बनाने का काम जारी
- निजी नलकूप के बिजली बिलों में 100% की छूट
- 24 घंटे में ट्रांसफार्म बदलने की व्यवस्था

सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण

- महाकुंभ में दुनिया भर के 66.30 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी
- सर्वाधिक पर्यटक आगमन वाला प्रदेश बना यूपी
- अयोध्या, ब्रज, विंध्य, चित्रकूट और नैमिषारण्य में विकास परिषद का गठन
- अयोध्या राम मंदिर निर्माण, काशी की देव दीपावली, अयोध्या दीपोत्सव जैसे आयोजन

स्वास्थ्य सुविधाओं पर बल

- गरीब परिवारों को पांच लाख तक का निशुल्क चिकित्सा सुरक्षा कवच
- 5000 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों की स्थापना
- 75 जिलों में डायलिसिस की निशुल्क सुविधा
- मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से 49 लाख परिवार लाभान्वित

इस तरह से देखा जाए तो योगी सरकार ने अपने आठ साल के कार्यकाल में कई योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है। इसमें एक्सप्रेसवे के निर्माण हों या महाकुंभ जैसे आयोजन। ऐसे ही देश में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य। उत्तर प्रदेश इन कामों की वजह से पूरे देश में चर्चित रहा। आगे भी योगी सरकार का कार्यकाल बाकी है, जिस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न योजनाओं को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।

समृद्ध किसान, सशक्त प्रदेश

- पी.एम. किसान सम्मान निधि के तहत 2.86 करोड़ से अधिक किसानों को 80,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से अंतरित।
- 8 वर्षों में 46.50 लाख किसानों को अब तक 2,80,223 करोड़ रुपये का किया जा चुका है गन्ना मूल्य भुगतान। यह वर्ष 1995 से 15 मार्च 2017 (22 वर्ष) में हुए कुल भुगतान से 66,703 करोड़ रुपये अधिक है।
- वर्ष 2016-17 में गन्ने का कुल क्षेत्रफल 20.54 लाख हेक्टेयर था, जो 2024-25 में बढ़कर 29.66 लाख हेक्टेयर हो गया है।
- इसके परिणामस्वरूप किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे गन्ना किसानों की औसतन 370 रुपये प्रति कुन्तल की दर से प्रति हेक्टेयर 43,364 रुपये की अतिरिक्त आमदनी सुनिश्चित हुई है।
- 2016-17 में प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन जहां 72 टन था, वह 2024-25 में बढ़कर 85 टन प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जिससे किसानों को अधिक उपज और आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है।
- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितंबर 2019 से लागू है, जिससे 63 हजार से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 58.07 लाख किसानों को 47,535.09 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति दी गई है।
- पी.एम. कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को 76,189 से अधिक सोलर पंप आवंटित किए गए हैं।
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में 2.52 लाख किसानों को लाभार्थी कार्ड प्रदान किए गए हैं।
- फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 8,78,192.23 करोड़ रुपये का फसली ऋण वितरित किया गया है।
- प्रदेश के 49 जनपदों में 85,710 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती।
- मुख्यमंत्री कृषक कल्याणकारी योजना के तहत मंडी परिषद द्वारा 79,796 किसानों को 134.76 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है।
- किसानों की सुविधा के लिए मंडियों में प्री-अराइवल ई-पास की व्यवस्था लागू की गई है और व्यापारियों को डिजिटल भुगतान की सुविधा दी गई है।
- कृषि विकास दर 2016-17 में 8.6 प्रतिशत थी, जो 2023-24 में बढ़कर 13.7 प्रतिशत हो गई है।
- खाद्यान्न उत्पादकता 2016-17 में 27 कुंतल प्रति हेक्टेयर थी, जो 2023-24 में बढ़कर 31 कुंतल प्रति हेक्टेयर हो गई है।
- तिलहन उत्पादन 2016-17 में 12.40 लाख मीट्रिक टन था, जो 2023-24 में 128 प्रतिशत बढ़कर 28.31 लाख मीट्रिक टन हो गया है।
- वर्तमान में प्रदेश में 122 चीनी मिलें क्रियाशील हैं। 2017 से पहले चीनी मिलों की दैनिक पेराई क्षमता 7.50 लाख टीसीडी थी, जो अब बढ़कर 8.36 लाख टीसीडी हो गई है।
- मार्च 2017 से अब तक तीन नई चीनी मिलों की स्थापना, छह चीनी मिलों का पुनर्संचालन और 38 चीनी मिलों की क्षमता वृद्धि की गई है, जिससे 1.25 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है।
- कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2024-25 में लगभग 66 लाख कुंतल गुणवत्तापूर्ण बीज वितरित किए गए हैं।

सशक्त युवा, समृद्ध प्रदेश

- निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभिन्न आयोगों और भर्ती बोर्डों के माध्यम से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, जिसमें 1.38 लाख से अधिक महिलाएं भी शामिल हैं।
- रोजगार मिशन समिति का गठन प्रक्रियाधीन है, वहीं अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) में एकल अवसरीय पंजीकरण (OTR) व्यवस्था लागू कर दी गई है।
- उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन भी किया गया है।
- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में प्राप्त निवेश प्रस्तावों से 1 करोड़ 10 लाख से अधिक युवाओं के लिए रोजगार और सेवायोजन के अवसर सृजित।
- एमएसएमई सेक्टर में 1.65 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है।
- "एक जनपद-एक उत्पाद" योजना के तहत 2,54,887 लोगों को रोजगार।
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 28,419 युवाओं को लाभान्वित किया गया है, जिससे 2,27,352 रोजगार के अवसर सृजित।
- मिशन रोजगार के तहत अब तक 1,890 प्रवक्ताओं, 6,314 सहायक अध्यापकों और 219 प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की जा चुकी है।
- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में 3,68,076 पात्र लाभार्थियों को सहायता।
- स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 49.86 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित, 2 करोड़ युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।
- प्रदेश में 50 इनक्यूबेटर और 7,200 स्टार्टअप संचालित हो रहे हैं, जिससे युवाओं को नए अवसर मिल रहे हैं।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 29,296 इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिससे 2,34,368 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।
- मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत 1 लाख से अधिक युवाओं का उद्योगों और अधिष्ठानों में पंजीकरण कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- आईटीआई और कौशल विकास मिशन के तहत 25 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षित किया गया है, जिससे 10.20 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है।
- इंडस्ट्री 4.0 के अनुरूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस्ड कंप्यूटिंग (रोबोटिक्स) जैसे उभरते क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- ऋण प्रवाह अभियान के तहत 37,000 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरित किया गया है।
- स्वरोजगार संगम कार्यक्रम में 22,319 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है।

भाजपा लोकदरबार में....

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार के 08 वर्षों की उपलब्धियों का उत्सव मनाएगी। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार की अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति, गांव, गरीब, किसान, महिला व युवाओं के सामाजिक व आर्थिक उन्नति को समर्पित सरकार की योजनाएं तथा भारतीय सांस्कृतिक जयघोष समेत अन्त्योदय की नीति तथा साहसिक निर्णयों को लेकर भाजपा लोक दरबार में पहुंचेगी। भाजपा आगामी 24 मार्च से 14 अप्रैल तक प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश सरकार की 08 वर्ष की उपलब्धियों के साथ जनसंवाद करेगी। उपाध्यक्ष श्री मानवेन्द्र सिंह, प्रदेश मंत्री श्री शंकर गिरि, श्रीमती मीना चौबे, श्री अमित वाल्मीकि, श्री बसन्त त्यागी और श्री शिवभूषण सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही क्षेत्र व जिला स्तर पर भी संयोजक व सहसंयोजक बनाए गए है।

श्री शुक्ल ने बताया कि अभियान के तहत जिला स्तर लाभार्थी मेले आयोजित किये जायेंगे। घर–घर सम्पर्क के माध्यम से भी सरकार की योजनाओं तथा साहसिक व ऐतिहासिक निर्णयों को घर–घर व जन–जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा स्तर पर विकास गोष्ठियां भी आयोजित की जायेंगी, जिनमें 8 वर्ष की विकास यात्रा पर चर्चा होगी। युवा मोर्चा जिले में

अभियान की दृष्टि से जिला स्तर पर 23 व 24 मार्च को कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी।

अभियान के प्रदेश संयोजक व प्रदेश महामंत्री श्री गोविन्द नारायण शुक्ल ने बताया कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी एवं प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री धर्मपाल सिंह द्वारा तय कार्ययोजना के अनुसार "उत्तर प्रदेश का उत्कर्ष–भाजपा सरकार के 08 वर्ष" के संदेश के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर भाजपा जनमानस तक पहुंचेगी। अभियान के लिए प्रदेश स्तर पर प्रदेश महामंत्री श्री गोविन्द नारायण शुक्ल, प्रदेश सरकार की प्रमुख परियोजनाओं पर बाइक रैलियों के माध्यम से पहुंचेगा। जिला स्तर पर प्रबुद्धवर्ग के बीच सम्मेलनों के माध्यम से सरकार की 8 वर्ष की उपलब्धियों पर संवाद किया जाएगा। वहीं ग्राम सभा स्तर पर महिला मोर्चा महिलाओं के बीच पहुंचकर संवाद करेगी। 14 अप्रैल बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जयन्ती पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा तथा स्वच्छता कार्यक्रम बूथ स्तर पर आयोजित किए जाएगें। इसके साथ ही भाजपा सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं सामाजिक समरसता के लिए किये गए कार्यों पर चर्चा की जाएगी

आठ साल में ऐतिहासिक बड़े बदलाव : केशव

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व व निर्देशन में ग्राम्य विकास विभाग नये प्रतिमान स्थापित करते हुए विकास की नयी ऊंचाइयों को छू रहा है। ग्राम्य विकास विभाग की तमाम योजनाओं में उत्तर प्रदेश देश में टाप पर है और कई योजनाओं में उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा पुरूस्कृत किया गया है।

उत्तर प्रदेश की वर्तमान प्रदेश सरकार को 8 साल पूरे हो गए हैं। इन 8 सालों में प्रदेश में कई क्षेत्रों में बड़े बदलाव हुए हैं। प्रदेश सरकार ने इन आठ वर्षों में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महात्मा गांधी नरेगा योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में अब तक मनरेगा योजना के अंतर्गत धनराशि व्यय, मानव दिवस सृजन, 100 दिवस का रोजगार, अमृत सरोवर निर्माण, एरिया ऑफिसर एप के माध्यम से निरीक्षण आदि बिन्दुओं पर उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है और पहले पायदान पर खड़ा है।

प्रदेश में वर्तमान सरकार के 08 साल पूरे हो गये हैं। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के कुशल मार्गदर्शन में ग्रामीण विकास हेतु लगातार बेहतर कार्य किये जा रहे हैं। गांवों की आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने के साथ–साथ इच्छुक नागरिकों को गांव में ही मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य एवं लाभ उपलब्ध कराकर उन आजीविका को आसान बनाया जा रहा है।

'8 साल में 73 हजार करोड़ से ज्यादा खर्च'

बीते 08 वर्षों की बात करें तो मनरेगा योजना के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों पर वित्तीय वर्ष 2017–18 से अब तक 73,129 करोड़ से ज्यादा की धनराशि व्यय की गई है।

'8 साल में 234 करोड़ से ज्यादा मानव दिवस सृजित'

मनरेगा योजना के अंतर्गत मानव दिवस सृजन के मामले में उत्तर प्रदेश लगातार अग्रणी राज्य की भूमिका निभा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में अब तक प्रदेश में 32.89 करोड़ से ज्यादा मानव दिवस सृजित कर लिये गये हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में 26 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 32.89 करोड़ मानव दिवस सृजन कर प्रदेश में देश में सबसे आगे है। वहीं 2017–18 से अब तक प्रदेश द्वारा 234 करोड़ से ज्यादा मानव दिवस सृजित किये गये हैं।

'मनरेगा में महिलाओं का लगा मन'

महिलाओं का मन अब मनरेगा के कार्यों में तेजी से लग रहा है। इसलिए महिलाएं अब घर की चौखट पार कर काम करने के लिए बाहर निकल रहीं हैं। मनरेगा योजना के अंतर्गत महिलाओं को काम देने में प्रदेश द्वारा लगातार बेहतर प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में अब तक मनरेगा योजना के तहत कुल 32.89 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए, जिनमें से 13 करोड़ से ज्यादा महिलाओं का योगदान है, जो लगभग 42 प्रतिशत है। महिला मेट मनरेगा में प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिए महिला श्रमिकों के लिए सहायक सिद्ध हो रही हैं। वर्ष 2017–18 से अब तक महिलाओं द्वारा 87.66 करोड़ से ज्यादा मानव दिवस सृजित किये गये हैं।

'दिव्यांगजनों के लिए मनरेगा वरदान'

बीते 8 सालों की बात करें तो शारीरिक रूप से दिव्यांग जनों

के लिए मनरेगा योजना वरदान साबित हो रही है। आंकड़े बताते हैं कि बीते इन 8 वर्षों में 1.26 लाख से ज्यादा दिव्यांग जनों को योजना के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

'लाखों परिवारों को मिल रहा रोजगार'

गांवों के इच्छुक वयस्क नागरिकों को उनकी मांग के अनुरूप प्रत्येक वर्ष लाखों परिवारों को मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2017–18 से अब तक 5.26 करोड़ से ज्यादा ऐसे परिवार हैं, जिनकों बीते 08 वर्षों में मनरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध हुआ है।

'गांवों में समृद्धि के खुले नये द्वार'

भारत की आत्मा गांवों में बसती है। देश तभी समृद्ध होगा,जब गांव समृद्ध होंगे। मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों को समृद्ध करने का काम रही है। गांवों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बढ़ाने एवं आधारभूत संचरना को मजबूत बनाने का प्रयास निरंतर जारी है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्र, खेल मैदान, मनरेगा पार्क, पंचायत भवन, आंतरिक गलियां में नाली, खड़ंजा, सीसीरोड, स्कूलों की बाउंड्रीवॉल, खाद्यान्न भंडारण हेतु अन्नपूर्णा भवन आदि का निर्माण कराकर गांवों की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्राम्य विकास विभाग की ओर से बनाई गई कार्य योजना से खेल मैदानों का निर्माण हो रहा है। बीते वर्षों से प्रदेश में लगातार खेल मैदानों का निर्माण किया जा रहा है। बात करें अगर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 की तो इस वर्ष 5400 से ज्यादा खेल मैदानों का निर्माण किया जा चुका है जबकि 14 हजार से ज्यादा On Going कंडीशन में हैं। वर्ष 2017–18 से अब तक 21 हजार से ज्यादा खेल मैदान बनाये जा चुके हैं।

आयुक्त, ग्राम्य विकास श्री जी0एस0 प्रियदर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की संचालित योजनाओं के माध्यम से गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने एवं गांव की आधारभूत सुविधाओं का बढ़ाने हेतु मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य कराये जा रहे हैं। योजना के अतंर्गत होने वाले कार्यों में पारदर्शिता एवं निगरानी हेतु मनरेगा लोकपाल, स्टेट क्वालिटी मॉनीटर तैनात किये गये हैं, वहीं NMMS, एरिया ऑफिसर एप व ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल से बेहतर अनुश्रवण कर कार्यों को गुणवत्तापरक बनाया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी केन्द्र, खेल मैदान, मनरेगा पार्क, पंचायत भवन, आंतरिक गलियां में नाली, खड़ंजा, सीसीरोड, स्कूलों की बाउंड्रीवॉल, खाद्य भंडारण हेतु अन्नपूर्णा भवन, अमृत सरोवर, खेत तालाब आदि का निर्माण कराकर गांव व गरीबों को हर तरह से सशक्त और समृद्ध करने का प्रयास जारी है।

उत्कर्ष के आठ वर्ष के लिए बधाई

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी एवं प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री धर्मपाल सिंह ने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को सबका साथ–सबका विकास की नीति व अपराध पर जीरो टॉलरेंस के संकल्प के साथ प्रदेश भाजपा सरकार के सफलतम 08 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई दी है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि 2017 में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के नए युग का आरंभ हुआ था, जहाँ सुरक्षा, सुशासन एवं विकास की नीतियों से राज्य को एक नई दिशा मिली। इन 8 वर्षों में प्रदेश सरकार ने अनेकों जनकल्याणकारी कार्य किए, जिनके द्वारा राज्य के प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। प्रदेश सरकार की सुदृढ़ कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अपराध तथा अपराधियों के विरूद्व जीरो टॉलरेंस की नीति ने महिला, युवा, व्यापारी, किसान सहित सभी प्रदेशवासियों को सुरक्षा की गारंटी दी है। श्री चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के उत्कर्ष के आठ वर्ष में प्रदेश में भयमुक्त वातावरण में रिफार्म, परफार्म तथा ट्रांसफार्म के मंत्र के साथ निवेश का वातावरण बना है, जिससे प्रदेश के युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार के अवसर मिल रहे है। अन्नदाता के उत्थान के संकल्प से प्रदेश सरकार की योजनाएं किसानों को समर्पित रही। गन्ना किसानों के भुगतान से गन्ना किसान समृद्व हुए है। हर खेत को पानी के संकल्प को पूर्ण करने की ओर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाजपा सरकार से प्रदेश में सशक्त नारी से समृद्ध समाज की अवधारणा मजबूत हुई है। प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा और खाद्यान की प्रतिबद्धता के साथ काम करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अन्त्योदय को साकार रूप दे रही है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी सहित उनकी पूरी टीम को उत्तर प्रदेश के उत्कर्ष के आठ वर्ष के लिए बधाई।

संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो...

विश्व का सबसे बड़ा राजनैतिक दल जो अपनी लोकतांत्रिक संगठन व्यवस्था के लिए भी जाना जाता है। ऐसे में सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में लम्बी प्रक्रिया के बाद संगठनात्मक चुनाव हो रहे हैं। अधिसंख्यक मंडलों के चुनाव में भी प्रदेश की चुनाव समिति का मार्ग दर्शन रहा, जिसके कारण सामाजिक, क्षेत्रीय समीकरण का सन्तुलन में 1918 मंडलों में से अधिकांश के चुनाव शांतिपूर्वक हो गये। इन चुनावों में प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉ0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, श्री अरूण कान्त त्रिपाठी की अनथक साधना परिश्रम रहा।

जिलाध्यक्षों के चुनावी प्रक्रिया में प्रशासनिक 75 जिलों को भाजपा ने 98 संगठनात्मक जिले बनाया है जिसमें भारी संख्या में कार्यकताओं के नामांकन किया। श्री धर्मपाल सिंह जी ने सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं से वार्ता, गुणदोष का अध्ययन करने के बाद जो अध्यक्षों की सर्वसम्मति से नियुक्तियाँ हुई जिसके कारण पूरे प्रदेश में उत्साह का वातावरण है। सामाजिक, क्षेत्रीय सन्तुलन भी चुनाव में राजनैतिक सफलता दिलाने वाले हैं। ये संगठनात्मक चुनाव अगामी होने वाले चुनावों में भाजपा को निश्चित सफलता की ओर ले जायेंगे।

- श्रावस्ती – मिश्री लाल वर्मा
- उन्नाव – अनुराग अवस्थी
- वाराणसी महानगर से प्रदीप अग्रहरि
- ग़ाज़ीपुर से ओमप्रकाश राय
- प्रतापगढ़ से आशीष श्रीवास्तव
- भदोही से दीपक मिश्रा
- मछलीशहर से डा अजय कुमार सिंह
- सुल्तानपुर से सुशील त्रिपाठी
- अमेठी से सुधांशु शुक्ला
- प्रयागराज गंगापार से निर्मला पासवान
- प्रयागराज यमुनापार से राजेश शुक्ला
- प्रयागराज महानगर से संजय गुप्ता
- सोनभद्र से नन्दलाल गुप्ता
- गोरखपुर ज़िला – जनार्दन तिवारी
- गोरखपुर महानगर से देवेश श्रीवास्तव
- आज़मगढ़ से ध्रुव कुमार सिंह
- लालगंज से विनोद राजभर
- संत कबीरनगर से नीतू सिंह
- महाराजगंज से संजय पांडेय
- मऊ से रामाश्रय मौर्य
- कुशीनगर से दुर्गेश राय
- बस्ती से विवेकानंद मिश्रा
- बलिया से संजय मिश्रा
- आगरा ज़िला श्री प्रशांत पौनिया
- आगरा महानगर से राजकुमार गुप्ता
- मथुरा ज़िला से निर्भय पाडेय
- मथुरामहानगर से हरिशंकर राजू यादव
- फ़िरोज़ाबादमहानगर से सतीश दिवाकर
- मैनपुरी से ममता सिंह राजपूत
- कासगंज से नीरज शर्मा
- बरेली जिला से सोमपाल शर्मा
- बरेली महानगर से अधीर सक्सेना
- गौतमबुद्ध नगर – श्री अभिषेक शर्मा
- नोएडा महानगर – श्री महेश चौहान
- रामपुर – श्री हरीश गंगवार
- मुरादाबाद जिला – श्री आकाश पाल
- मुरादाबादमहानगर– श्री गिरीश मंडला
- बिजनौर – भूपेन्द्र सिंह चौहान 'बॉबी'
- सहारनपुर महानगर– शीतल विष्णोई
- मुज़फ़्फ़रनगर– सुधीर सैनी
- मेरठमहानगर– विवेक रस्तोगी
- गाज़ियाबाद जिला चैनपाल सिंह
- गाज़ियाबाद महानगर मयंक गोयल
- संभल से हरेंद्र चौधरी
- बुलन्दशहर से विकास चौहान
- कानपुरमहानगरउत्तर से अनिल दीक्षित
- कानपुरमहानगरदक्षिण से शिवराम सिंह
- कानपुर देहात से रेणुका सचान
- कानपुरग्रामीण से उपेन्द्र नाथ पासवान
- इटावा से अरुण कुमार गुप्ता "अन्नू"
- कन्नौज से वीर कुमार सिंह भदौरिया
- फ़र्रुखाबाद से फतेहचंद वर्मा
- औरैया से सर्वेश कठेरिया
- झाँसी ज़िला से श्री प्रदीप पटेल
- बांदा से कल्लू राजपूत
- महोबा से मोहनलाल कुशवाह
- चित्रकूट से महेन्द्र कोटार्य
- लखनऊ जिला से विजय मौर्य
- लखनऊ महानगर से आनंद द्विवेदी
- रायबरेली से बुद्धिलाल पासी
- हरदोई से अजीत सिंह 'बब्बन'
- बलरामपुर से रवि मिश्रा
- बहराइच ब्रजेश पांडेय
- गोंडा अमर किशोर कश्यप

एवं

पत्रिका पंजीकरण – RNI-51899/91, शीर्षक कोडः UPHIN16701, डाक पंजीकरण – SSP/LW/NP-117-2024-26
मार्च द्वितीय अंक 2025 –प्रेषित डाकघर –R.M.S. चारबाग, लखनऊ –प्रेषण तिथि : 26–29 (द्वितीय पाक्षिक)

भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्रक तथा प्रकाशक प्रो. श्यामनन्दन सिंह द्वारा नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र, संस्कृति भवन, राजेन्द्र नगर, लखनऊ से मुद्रित व भाजपा कार्यालय, 7, विधानसभा मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित।